

संक्षिप्त समाचार

पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रह्लाद दास की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, वारदात की जांच के सिलसिले में आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां उसने एक पुलिस अधिकारी का सरकारी हथियार छीनकर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना रात के समय हुई, जब जांच दल आरोपी से वारदात के घटनाक्रम की जानकारी लेने और घटनास्थल पर पूरी घटना को दोहराने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और गोली चला दी।

गुवाहाटी के होटल में गोलीबारी, एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच की मौत

गुवाहाटी। असम की राजधानी गुवाहाटी में देर रात हुई गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं। घटना बोरा सर्विस इलाके में स्थित होटल बिलास इन में हुई। पुलिस के अनुसार, होटल के मालिक और होटल को पट्टे पर लेने वाले घनकांत गोगोई के बीच विवाद के बाद गोलीबारी हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लाइसेंस, .32 बोर की पिस्तौल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, घनकांत गोगोई ने पिछले वर्ष होटल पट्टे पर लिया था। इस वर्ष पट्टा समझौते को लेकर होटल मालिक और गोगोई के बीच विवाद चल रहा था। सोमवार रात दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। इसके बाद गोगोई ने कथित तौर पर गोलीबारी कर दी, जिसमें होटल की मालकिन और उनके परिवार के सदस्यों सहित पांच लोगों की जान चली गई।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने तंज भरे जवाब के लिए माफी मांगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सामाजिक माध्यम 'एक्स' पर राजनेताओं को दिए गए तंज भरे जवाबों के लिए माफी मांगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से हिंदी और अंग्रेजी में माफी संदेश जारी किया गया। कार्यालय ने स्वीकार किया कि संबंधित पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा, उसका भाव और तीखापन एक आधिकारिक खाते से अपेक्षित संवाद के अनुरूप नहीं था। साथ ही भविष्य में संवाद को शांलीन और औपचारिक रखने की बात कही गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि संबंधित पोस्ट को टिप्पणियों से लोगों में उत्पन्न नाराजगी को गंभीरता से लिया गया है। कार्यालय ने लिखा कि वह उन लोगों से ईमानदारी से माफी मांगता है।

साइक्लोन अर्नब का तांडव

आंध्र प्रदेश में चक्रवात से सात लोगों मौत, 50 ट्रेनें रद्द

नई दिल्ली/ एजेंसी

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' बुधवार तड़के आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। तूफान के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और कई इलाकों में भारी बारिश हुई। चक्रवात के असर से रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने 50 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से जुड़ी 21 उड़ानें भी रद्द की गई हैं। खबरों के मुताबिक, तूफान के कारण आंध्र प्रदेश में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 84 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि ओडिशा में भी हजारों लोगों को शिफ्ट

किया गया है। तूफान के असर से ट्रेनें और उड़ानें रद्द हुई हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में करीब 4,000 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं। ओडिशा में भारी बारिश की आशंका के चलते 16 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य में करीब 30 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विशाखापत्तनम में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 27 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक करीब 18 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। यह शहर में जुलाई के



औसत मासिक बारिश के आंकड़े 133 मिलीमीटर से डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार सुबह 9:50 बजे जारी बुलेटिन में बताया कि 'अर्नब' बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आंध्र प्रदेश और यनम के तटों के ऊपर सक्रिय था। लैंडफॉल की प्रक्रिया छह घंटे से अधिक

पुजारी ने संभावित प्रभावित क्षेत्रों से करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 4,072 गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है, जिनमें से करीब 2,000 को अस्पतालों और चक्रवात आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया था। दोनों आंकड़े अलग-अलग समय पर जारी किए गए बयानों से संबंधित हैं। आईएमडी के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने चेतावनी दी है कि चक्रवात की धीमी गति के कारण दक्षिणी ओडिशा में बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की आशंका जताई गई है।

पेंडा में चक्रवात 'अर्नब' का असर: तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट

पेंडा। क्तीसगढ़ के पेंडा जिले में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर दिखाई देने लगा है। पिछले दो दिनों से आरम्भन में बादल छाए रहने और सूरज की आंख-मिचौली के बाद बुधवार दोपहर जिले में तेज बारिश शुरू हो गई। देर रात से ही मौसम में ठंडक महसूस की जाने लगी थी। वहीं, दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर होते-होते तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। अवानक बदले मौसम के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने की संभावना है। मौसम में आई ठंडक के चलते राई, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने से ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

टहलने निकली युवती की ओवरब्रिज से गिरकर मौत

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बुधवार सुबह पावर हाउस ओवरब्रिज से गिरने के बाद एक युवती की मौत हो गई। मृतका की पहचान शिवाजी नगर, खुर्सीपार निवासी पूनम अहिरवार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद छवनी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती ओवरब्रिज से दुर्घटनाग्रस्त गिरी या मामला आत्महत्या से जुड़ा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पूनम अहिरवार घर से टहलने के लिए निकली थी। इसके बाद परिजनों को पुलिस के माध्यम से उसकी मौत की जानकारी मिली।



घटना की खबर मिलने पर परिवार में शोक का माहौल है। युवती पावर हाउस ओवरब्रिज तक कैसे पहुंची और वहां किन परिस्थितियों में गिरी, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार, पूनम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उसे झटके आने की समस्या भी थी।

सरकारी रेलवे कंपनी रेलफे की एवीई ट्रेन सामने खड़ी इरियो ट्रेन से पीछे से टकरा गई

स्पेन में भीषण रेल हादसा-दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 64 लोगों की मौत, कई घायल, रेल सेवा ठप

नई दिल्ली। स्पेन के टोलेडो प्रांत में बुधवार, 28 अक्टूबर को दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसा उर्दा के पास हुआ, जहां सरकारी रेलवे कंपनी रेलफे की एवीई ट्रेन सामने खड़ी इरियो ट्रेन से पीछे से टकरा गई। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतरकर ढलान पर जा गिरे। हादसे के कारण मैड्रिड और अंखलूसिया के बीच हाई-स्पीड रेल सेवा रोक दी गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। स्पेन के रेल नेटवर्क ऑपरेटर एडीआईएफ के

अनुसार, बुधवार सुबह करीब 8:54 बजे टोलेडो प्रांत में दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर हुई। दोनों ट्रेनें मैड्रिड से सेविले जा रही थीं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रेलफे की एवीई ट्रेन ने आगे खड़ी इरियो ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और ढलान पर जा गिरे। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। आपातकालीन सेवाओं की टीमों घायलों को निकालने और उन्हें चिकित्सा सहायता पहुंचाने में जुट गईं। कैस्टिला-ला मांचा क्षेत्र की



प्रवका एस्तेर पैडिला के मुताबिक, रेलफे की एवीई ट्रेन में 397 यात्री सवार थे, जबकि इरियो ट्रेन में 147 यात्री थे। हादसे में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। इरियो कंपनी ने कहा कि उसने

अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए हैं और राहत कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे के पीछे तकनीकी खराबी

और मानवीय भूल की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी में सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ी समस्या का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, दुर्घटना के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रेलफे की ट्रेन आगे खड़ी इरियो ट्रेन से कैसे टकराई। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हादसे पर गहरा दुःख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू पर कहा कि टोलेडो में हुई इस गंभीर रेल दुर्घटना से वह स्तब्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

चुनाव आयोग फार्म 6, 7 और 8 में ख़ुद नहीं कर सकता बदलाव-कोर्ट

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदाता सूची का शुद्धिकरण और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्वाचन पंजीकरण नियमों के तहत वैधानिक फॉर्म तय किए गए हैं, जिनमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 और पते या विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 का उपयोग होता है। इन निर्धारित फॉर्मों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का कानूनी अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चुनाव आयोग



द्वारा ख़ुद के नाम पर चलाए जा रहे सचन सत्यापन अभियान के दौरान इन फॉर्मों के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़ने और पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम कटने पर उनसे दोबारा नए वोटर वाला फॉर्म 6 भ्रवाने का नियम लागू किया गया था। इस प्रक्रिया से लाखों वास्तविक मतदाताओं

के मताधिकार पर संकट खड़ा हो गया और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों समेत याचिकाकर्ताओं ने इसे गैर-कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की चौखट खटखटा दी। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने दिल्ली एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारों की सीमा रेखा तय कर दी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से वैधानिक फॉर्म 6, 7 और 8 को कानूनी बनावट या शर्तों में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। सीधे अदालत ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि आयोग ने अपनी ओर से पुरानी सूचियों और वंशावली से जुड़े अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़कर प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया।

टाटा संस में नेतृत्व विवाद फिर गहराया, नोएल टाटा ने चेयरमैन पद पर चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को दी चुनौती

नई दिल्ली। टाटा समूह की होलिंग कंपनी टाटा संस में नेतृत्व को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। नोएल टाटा ने कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देते हुए दावा किया है कि इस फैसले में कई प्रक्रियागत खामियां हैं और संभावित हितों के टकराव से जुड़े सवालों को नजरअंदाज किया गया है। कंपनी सचिव सुप्रकाश मुहोपाध्याय को भेजे गए एक पत्र में नोएल टाटा ने सात दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस प्रस्ताव के जरिए चंद्रशेखरन को 21 फरवरी 2027 से अगले पांच वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया।

सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद

नागरिकता मिलने से पहले कैसे जुड़ा नाम, 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत के कानून के अनुसार, देश की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोट डालने का पहला नियम यही है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ यह पुराना विवाद अब एक बार फिर कानूनी रूप से जिंदा हो गया है। एक वकील ने अदालत में दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि सोनिया गांधी लेकिन अब ऊपरी अदालत यानी सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पूरी तरह गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिससे



चुका था। निचली अदालत ने पहले इस शिकायत को यह कहकर खारिज कर दिया था कि सबूतों के रूप में सिर्फ फोटोकॉपी दी गई है। लेकिन अब ऊपरी अदालत यानी सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पूरी तरह गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिससे

यह कानूनी मामला दोबारा अदालत की चौखट पर आ पहुंचा है। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी थी। हालांकि, बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों की हड़ताल की वजह से अदालती काम ठप रहा और मामले में जिरह आगे नहीं बढ़ सकी। कोर्ट ने स्थिति को देखते हुए सुनवाई के लिए 6 नवंबर की नई तारीख तय कर दी है। इसी दिन तय होगा कि मामले में आगे की कानूनी जांच किस दिशा में बढ़ेगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सेशंस कोर्ट ने निचली मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को पलट दिया।

एमएलसी चुनाव : 4 राज्यों की 28 सीटों पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला

पीएम मोदी ने कसा तंज-जहां सरकार वहां भी झटका, राहुल का क्या होगा

नई दिल्ली/ एजेंसी

बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 28 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफहो गया है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापने वाली कांग्रेस बिहार-यूपी ही नहीं कर्नाटक में भी 'शून्य' पर सिमट गई। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल के टीचर्स और ग्रेजुएट्स के कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ। चारों सीटों पर बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने परचम लहराते हुए जीत हासिल की। जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगियों ने जीत हासिल कर इज्जत बचाई। कर्नाटक में एक भी सीट नहीं जीतने पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल

गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस ने चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों में से 12 पर चुनाव लड़ा था और सभी पर हार गई है। यूपी में कांग्रेस ने 11 सीटों में से कहीं चुनाव नहीं लड़ा था। कर्नाटक में अपनी सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। महाराष्ट्र में 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। यहां पर काउंटिंग अभी जारी है लेकिन तीनों सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। बिहार में कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहां भी सभी सीटों पर हार गई है। वहीं कुल 28 विधानपरिषद चुनावों में 21 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। इसमें से 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की या फिर आगे चल रही है। कांग्रेस का सबसे खराब



परफॉर्मेंस कर्नाटक में रहा। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। यहां चार सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। हमेशा बैलेट पेपर से चुनाव का राग अलापने वाली कांग्रेस एमएलसी चुनाव में बीजेपी के सामने चारो खाने चित हो गई। बीजेपी के

हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के पुराने साथी तंज कस रहे हैं। साथ ही हार मर मजा ले रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी सीएम की एक पुरानी तस्वीर भी पेपर से चुनाव का राग अलापने वाली कांग्रेस एमएलसी चुनाव में बीजेपी के सामने चारो खाने चित हो गई। बीजेपी के

में थे और उन्होंने तब के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पेश किए गए राज्य बजट के खिलाफ विधानसभा के अंदर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा ने अब इसी फोटो का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस नेताओं पर 'लीपापोती' का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने के बाद भी उनकी हालत ऐसी ही है। बता दें कि सभी चार सीटों पर 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में मतदान बैलेट पेपर के जरिए किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक मतगणना के बाद नतीजे साफहो गए और विपक्षी गठबंधन ने सभी सीटें अपने कब्जे में ले लीं। नतीजों के बाद जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा।

वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी क्यों अहम है?

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की टिप्पणी के संदर्भ में इन नतीजों को कांग्रेस के लिए आत्ममंथन के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि हकीकत की पड़ताल 28 एमएलसी सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इसमें कर्नाटक में एक मौजूदा सदस्य की सीट का नुकसान भी शामिल है। एमएलसी चुनाव भले ही मतदाताओं के मुँह को सीधे तौर पर न द्वांते हों, लेकिन इनसे क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों, पार्टी संगठन और रणनीति स्तर पर कांग्रेस के सामने मौजूद चुनौतियों का संकेत जरूर मिलता है। 28 सीटों पर एक भी जीत न मिलना एक ऐसा नतीजा है जिसे पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन नतीजों से कांग्रेस के सामने संगठनात्मक और क्षेत्रीय स्तर पर राखत जरूर खड़े होते हैं। 28 सीटों पर कांग्रेस की हार पार्टी के लिए एक राजनीतिक झटका है।

संक्षिप्त समाचार

बल मर्डर का खुलासा : शराब में जहर मिलाकर दो ग्रामीणों की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में दो ग्रामीणों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी राजा उर्फ कमलनाथ खरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पैसों के लेनदेन और आपसी विवाद के चलते आरोपी ने कथित तौर पर शराब में जहरिला पदार्थ मिलाकर दो ग्रामीणों को पिला दिया था। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को रात ग्राम कुटराबोड़ में हटली पेड़ के पास स्थित चबूतरा दुकान में ग्राम पामगढ़ निवासी जोहित खरे और ग्राम नवागढ़ निवासी रामसहिलावन जांगड़े ने शराब पी थी। इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए बिलासपुर के अग्रहो अस्पताल और सिस्म में भर्ती कराया गया, जहां 24 अक्टूबर को दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पामगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की और मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान जोहित खरे की बेटी मनीषा खरे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने 4 मई 2026 को राजा उर्फ कमलनाथ खरे से घरेलू खर्च के लिए 10 लाख रुपये उधार लिए थे। एकम को वापसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर की रात आरोपी ने दोनों ग्रामीणों को फेन कर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद उन्होंने शराब का सेवन किया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। जांच में शराब में जहरिला पदार्थ मिलाए जाने की बात सामने आई। परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामले में साक्ष्य जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

स्मृति ईरानी के दौर से पहले पोस्टर वार, गैस सिलेंडर के मुद्दे पर कांग्रेस का तंज-अजय चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नवनिर्जुत प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दौर को लेकर सियासत तेज हो गई है। उनके आगमन से पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी कर गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की पोस्टर राजनीति को शर्मनाक बताते हुए पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से जारी पोस्टर में स्मृति ईरानी को गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चलाते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते दिखाया गया है। पोस्टर पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने का जिक्र करते हुए 'अंधभक्तों में खुशी की लहर' का कैप्शन दिया गया है। कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भाजपा पर व्यंग्य किया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास जनता के बीच रखने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है और वह मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने में लगी है। चंद्राकर ने कहा कि पोस्टर के जरिए केवल औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की गई है। स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौर से पहले सामने आए इस पोस्टर ने भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज कर दी है। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर शुरू हुई यह सियासी बहस अब सोशल मीडिया पोस्टर और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के जरिए चर्चा में है।

रायपुर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता ‘वोट बचाओ,देश बचाओ’अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

रायपुर। केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी दलों द्वारा निर्वाचन आयोग के माध्यम से कथित वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी मैदान में प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी का पक्ष रखा और मतदाता सूची की पारदर्शिता तथा निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पर्यवेक्षक एवं लोकसभा सांसद शोभा बच्चाव, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय जाँगिड़, पर्यवेक्षक अरुण चोरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पन्पू बंजारे सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में सांसद शोभा बच्चाव ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा केवल वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने विभिन्न चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने, दोहरी पंजीयन व्यवस्था, चुनाव संबंधी आँकड़ों की पारदर्शिता, वीवीपैट की कार्यप्रणाली और निर्वाचन आयोग के आचरण को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर पा रहा है और क्या चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत कराए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा और लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ में हुए शामिल

किसानों का परिश्रम ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का आधार-मुख्यमंत्री

■ सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर, दो वर्षों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत

■ 1,500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपए स्वीकृत, 76 हजार हेक्टेयर बढ़ेगा सिंचित रकबा

रायपुर/ संवाददाता

किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार खेती-किसानी है।

छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम,30 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार..

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में ठंड की शुरुआत के बीच एक बार फिर मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं, 28 से 30 अक्टूबर के बीच कुछ इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश होने के आसार हैं। इस संभावित बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में फिलहाल ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि सुबह और रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का अहसास होने लगा है। ऐसे में महीने के अंत में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की गतिविधियां मौसम का मिजाज बदल सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र 25 अक्टूबर तक गहरे अवदाब

अवदाता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, खेती की लागत कम हो और सिंचाई सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में श्रेष्ठय मनहरण लाल पाण्डेय की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान से सम्मानित किया और कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। इसलिए किसानों की खुशहाली से ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है।



मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और खरीदी केंद्रों पर दबाव भी कम होगा। इससे किसानों के समय और श्रम को

बचत होगी तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र किसान सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज बेच सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने समारोह में प्रदेशभर से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारे

शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार का आरोप, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

रायपुर। नाबालिग से अनाचार के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी करन कुमार सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जांजगीर थाना क्षेत्र के पिसौद गांव का निवासी है। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को पोंडिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार किया। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 91/2026 के तहत बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और विधिवत गिरफ्तार कर लिया।

खुले मैदानों को बचाने की मांग बीटीआई ग्राउंड पर प्रस्तावित निर्माण को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध...

रायपुर/ संवाददाता

राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजना को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस परियोजना का विरोध करते हुए मैदान को सार्वजनिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि शहर में खुले मैदानों की पहले से कमी है, ऐसे में उपलब्ध मैदानों का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए करने से आम नागरिकों की सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने

किसान परंपरागत खेती के साथ नई तकनीक और नवाचारों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे किसानों का सम्मान अन्य किसानों को भी बेहतर और ऊन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रेष्ठय मनहरण लाल पाण्डेय का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री पाण्डेय का संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि श्री पाण्डेय का खेती-किसानी और ग्रामीण जीवन से गहरा जुड़ाव था। उन्होंने विशेष रूप से सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वे हमारे प्रेरक और मार्गदर्शक रहे हैं। उनकी स्मृति में किसानों और समाजसेवियों को सम्मानित करने की यह पहल सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आয়োजन समिति को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों की आर्थिक जरूरतों को समझते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी।

खुले मैदानों को बचाने की मांग बीटीआई ग्राउंड पर प्रस्तावित निर्माण को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध...



कहा कि बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर क्षेत्र का महत्वपूर्ण खुला स्थान है, जहां लोग सुबह-शाम सैर करने के साथ खेलकूद और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। उनके अनुसार, इस स्थान पर व्यावसायिक और आवासीय निर्माण की योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा

कि शहर के विकास के साथ नागरिकों के लिए खुले स्थानों को बनाए रखना भी जरूरी है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि रायपुर में पहले भी स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के मैदानों में निर्माण तथा व्यावसायिक गतिविधियों के कारण खुले स्थानों की उपलब्धता कम हुई है। उन्होंने साइंस कॉलेज मैदान, सप्रे स्कूल, आरडी तिवारी स्कूल और मोबा सहित अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि शहर में खेलकूद और सार्वजनिक आयोजनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की जरूरत है। कांग्रेस का कहना है कि बीटीआई ग्राउंड बच्चों के खेलकूद और स्थानीय नागरिकों की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिक पशुपालन से आत्म निर्भरता की राह पर अनूप कश्यप



■ उन्नत नस्ल की गायों और बछियों से बढ़ी आय, पशुधन विकास विभाग की योजनाओं और तकनीकी मार्गदर्शन से मिला संबल

रायपुर/ संवाददाता

पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से अपनाना जाए तो यह ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आय और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज निवासी श्री अनूप कुमार कश्यप ने शासकीय योजनाओं और पशुधन विकास विभाग के सहयोग से अपने पशुपालन को नियमित आय के साधन में बदल दिया है। कभी घरेलू जरूरतों तक सीमित रहन उकाया पशुपालन अब उन्नत नस्ल की गायों और बछियों के साथ व्यवस्थित आजीविका का रूप ले चुका है। दूध की बिक्री से उन्हें नियमित आमदनी हो रही है। श्री कश्यप को इस प्रगति में पशुधन विकास विभाग के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृत्रिम

गर्भाधान से उनके पशुधन में उन्नत नस्ल की गायें और बछियाँ शामिल हुईं। विभागीय पशु चिकित्सक एवं मैदानी अमला समय-समय पर पशुओं का टीकाकरण और कुमिनाशक उपचार करते हैं। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम एवं विटामिन सफ़ोमीट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही, संतुलित आहार, देखभाल और पशु प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह दी जाती है। उन्नत मादा वत्स पालन योजना से मिली आर्थिक सहायता ने बछियों के पालन-पोषण को बेहतर बनाने में मदद की है। इन बछियों के भविष्य में दुधारू गाय बनने से उनकी आय में और वृद्धि की संभावना है। योजनाओं का लाभ और विभागीय सहयोग मिलने से श्री कश्यप अब आसपास के पशुपालकों को भी उन्नत नस्ल, समय पर टीकाकरण और संतुलित पोषण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बलरामपुर जिले में पशुधन को नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्त तीन वर्षों में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत जिले में 36 हजार से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 17 हजार से अधिक उन्नत नस्ल के बछड़े-बछियाँ का जन्म हुआ है।

रायपुर में अपराधों का सिलसिला: दुष्कर्म अवैध हथियार और हेरोइन के मामले दर्ज

रायपुर। संवाददाता

राजधानी रायपुर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दुष्कर्म, मकान और वाहन चोरी, सड़क दुर्घटना में मौत, जुआ, अवैध हथियार से हवाई फयरिंग और मादक पदार्थ रखने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने संबंधित शिकायतों के आधार पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, दोनों की पहचान कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी और उनके बीच प्रेम संबंध था। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की

धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया है। डीडो नगर थाना क्षेत्र के डगनिया में अज्ञात चोर ने सूने मकान का ताला तोड़कर आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर और एक लाख रुपये नकद चोरी कर लिए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 1.35 लाख रुपये बताई गई है। खमतराई थाना क्षेत्र की डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में खड़ी एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वाहन की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है। वहीं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्काईपाक बिल्डिंग के सामने पार्किंग से फैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसकी कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई गई है। गुडियारी थाना क्षेत्र के गोंदवारा ओवरब्रिज स्थित महतारी चौक के पास एक सूने मकान से एचपी कंपनी का लैपटॉप

चोरी होने का मामला भी सामने आया है। लैपटॉप की कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। डीडो नगर थाना क्षेत्र के कुम्हारपारा, रायपुरा में 24 अक्टूबर की सुबह एक वाहन की टक्कर से 80 वर्षीय बुधारू राम साहू की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे, तभी वाहन चालक ने कथित तौर पर तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र के सरजू बांधा तालाब के पास जुआ खेलने के ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

आत्मनिर्भर और बहुआयामी संस्था बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास

आधुनिक तकनीक और नवाचार से अधोसंरचना विकास को मिलेगी नई दिशा : आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी

■ अधिनियम संशोधन से मंडल के कार्यक्षेत्र, सोच और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव का अवसर : अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आधुनिक तकनीक, नवाचार और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर तथा बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।



इसी उद्देश्य से मंडल द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेशभर से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक निर्माण तकनीक,

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन, टाउन प्लानिंग स्कीम तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आवास एवं

पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि बदलते समय और विकास की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप मंडल को अपनी कार्यप्रणाली, तकनीकी दक्षता और कार्यक्षेत्र का विस्तार करना होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार मंडल को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, नवाचार, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनाकर मंडल प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई दिशा दे सकता है। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है।

संपादकीय

फ्रांस में युवाओं का आंदोलन शिक्षा की बदहाली, महंगाई और बढ़ते खर्च के खिलाफ गुस्से में बदल गया है। राजनीतिक बंटवारा, बढ़ता सरकारी राज और बुजुर्गों की पेंशन पर भारी खर्च सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। युवाओं की घटती राजनीतिक ताकत और बजटीय सीमाओं के बीच फ्रांस के आर्थिक व राजनीतिक संकट के गहराने का खतरा है। फ्रांस में लोगों का समय-समय पर आंदोलन करना आम बात है। वहां होने

वाले विरोध-प्रदर्शन अब हिंसा और तोड़फोड़ में तब्दील हो रहे हैं। काले कपड़े पहनने वाले ब्लैक ब्लॉक किसी खास एजेंडे के बजाय तोड़फोड़ के लिए कुख्यात हैं। इससे राजनीतिक बंटवारा, बढ़ता कर्ज और युवाओं की नाराजगी जैसी तीन बड़ी समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती। मार्स के मेयर ने भी कहा है कि तोड़फोड़ के कारण छात्रों की मूल समस्याएं अनसुनी रह जा रही हैं। स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की कमी से शुरू हुआ

विरोध अब महंगाई और बढ़ते खर्च के खिलाफ गुस्से में बदल गया है।यूरोप के अमीर देशों को इस बात पर सहमति बननी होगी कि देश के धन और संसाधनों का बंटवारा कैसे हो। फिल्लाल, बुजुर्गों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, जबकि युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यूरोप में जन्म दर घटने और औसत उम्र बढ़ने से युवाओं की आबादी कम हो रही है। ऐसे में फ्रांस और स्पेन में युवाओं की राजनीतिक ताकत भारत,

बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की तुलना में सीमित होती जा रही है।यूरोपीय देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी खर्च और कमाई के बीच संतुलन साधने की है। इसके लिए उन्हें या तो खर्च घटाना होगा या आमदनी बढ़ानी होगी। लेकिन, बुजुर्ग पेंशन में कटौती नहीं चाहते और सरकार का सबसे ज्यादा खर्च भी उसी पर है। इसके अलावा, वहां के लोग बाहरियों को बसाने के खिलाफ भी हैं। इससे सरकारों के लिए रास्ता

निकालना मुश्किल हो रहा है। फ्रांस के पास शिक्षा पर खर्च बढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ऐसे में टकराव बढ़ने का खतरा है। फ्रांस सरकार जीडीपी का 5.1 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है। इसके बावजूद स्कूलों की सुविधाएं सुधारने और पढ़ाई को बेहतर बनाने पर कम खर्च होता है, क्योंकि इसका एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा रिटायर्ड शिक्षकों की पेंशन में चला जाता है। राष्ट्रापति एमैनुएल मैक्रों ने सरकारी खर्च घटाने के

लिए 2023 में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला किया। लेकिन, इसका इतना विरोध हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा।बढ़ते सरकारी कर्ज के कारण वहां के निवेशकों की चिंता भी बढ़ रही है। सरकारी बॉन्ड की बिकवाली बढ़ने से फ्रांस के लिए कर्ज लेना महंगा हो गया है और ब्याज दरें 2.5 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में अगले साल के बजट से बड़े बदलाव की उम्मीद कम है।

क्या कभी आत्मदैन्य से मुक्त हो सकेंगे हम?

(प्रो. संजय द्विवेदी)
लंबे समय की गुलामी ने हमें आत्मदैन्य और आत्महीनता की ओर ढकेल दिया। भारतीय समाज के अपने पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर हम शासक वर्गों द्वारा थोपी जा रही संस्कृति का अनुगमन करने लगे। हमें लगा हमारे अंग्रेज शासक, उनकी भाषा, पहनावा और उनकी संस्कृति-पंथ सबकुछ हमसे बेहतर है।

कोई भी राष्ट्र जिस स्थिति में होता है, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। जापानी जैसे हैं ,उनका देश वैसा ही है। इसी तरह की बात इजरायल, चीन और ईरान या किसी भी देश के बारे में हो सकती है। भारत भी वैसा ही है, जैसे हम हैं ! ऐसे में कभी विदेशी आक्रांताओं,कभी मैकाले और कभी अपनी आजादी के बाद सत्ता में आए नायकों को कोसते हुए हम अपने कर्तव्यबोध से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों की सामूहिक चेतना के आधार पर विकसित होता है। उसका इतिहासबोध, संस्कृतिबोध, मित्रबोध और शत्रुबोध मिलकर उसका निर्माण करते हैं। इनसे ही राष्ट्रीय मानस या राष्ट्रीय भाव बनता है।

लंबे समय की गुलामी ने हमें आत्मदैन्य और आत्महीनता की ओर ढकेल दिया। भारतीय समाज के अपने पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर हम शासक वर्गों द्वारा थोपी जा रही संस्कृति का अनुगमन करने लगे। हमें लगा हमारे अंग्रेज शासक, उनकी भाषा, पहनावा और उनकी संस्कृति-पंथ सबकुछ हमसे बेहतर है। उनके अनुयायी बनकर ही हमारी मुक्ति है। तत्कालीन समाज के श्रेष्ठ जन भी ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटते थे और खुद को आधा-अधुरा अंग्रेज साबित करने में जुट जाते थे। ऐसे में शेष समाज अपने श्रेष्ठ वर्ग का आचरण देख वैसा ही बनने का प्रयास करने लगा। देश में तमाम सर, रायबहादुर और साहेब बहादुर हमारे आदर्श बन गए। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविन्द, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय,रवीन्द्र नाथ टैगोर के बहुत गहरे भारतबोध की प्रज्ञा ने हमें संभाला ,वर्ना हमारी दास्तां भी न होती दास्तानों में। हमारी हस्ती मिटने से कोई रोक नहीं सकता था। देसीउत्पाद खोजें

औसत भारतीय का आचरण अंग्रेजी शासनकाल में कैसा था, कहने की जरूरत नहीं है। हम कोहिनूर को छोड़कर कांच की ओर दौड़ रहे थे। अंग्रेजी भाषा और संस्कृति श्रेष्ठता की परिचायक बन गईं। जब तक अपना कोई व्यक्ति या कार्य पश्चिम में स्थापित न हो जाए, उसे हम श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजी शासन और उसके बाद के आजादी के साल भी आत्मगौरव के अभाव में गुजरे साल बनकर रह गए। सत्ता के आतंक और सत्ता से जुड़े रहने के आकर्षण से हमने अपने जीवन मूल्यों का सनातन सिद्ध राजमार्ग छोड़कर अंग्रेजियत की पागंडीयों पर चलना प्रारंभ कर दिया, जो हमारा देखा-परखा रास्ता नहीं था। जाहिर है इस मार्ग पर हम नेतृत्वकर्ता नहीं, अनुयायी ही बन सकते थे। हमारे एकत्व को चोटिल करने के सचेतन प्रयास प्रारंभ हुए। भारतीय शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी राज में कैसे नष्ट किया गया, इसे धर्मपाल जी को पढ़कर ही समझ में आएगा। स्व के स्थान पर परकीय विचारों की स्थापना के प्रयास खूब चले। हम एक राष्ट्र नहीं हैं, बताया गया। अनेक स्थानीयताओं को राष्ट्रीयता के बरक्स स्थापित करने के अकादमिक प्रयास भी खूब चले, सफल भी हुए। कैसे और कितने विभाजन गढ़े जा सकते हैं, सारा जोर इसी पर था। भारतीय ज्ञान परंपरा पर चल रहे लोगों के आत्मविश्वास की समाप्त होना इस पूरे विचार की ही गोंगापंथ और पिछड़ेपन के रूप में आरोपित किया जाना फैशन बन

लंबे समय की गुलामी ने हमें आत्मदैन्य और आत्महीनता की ओर ढकेल दिया । भारतीय समाज के अपने पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर हम शासक वर्गों द्वारा थोपी जा रही संस्कृति का अनुगमन करने लगे । हमें लगा हमारे अंग्रेज शासक, उनकी भाषा, पहनावा और उनकी संस्कृति-पंथ सबकुछ हमसे बेहतर है । उनके अनुयायी बनकर ही हमारी मुक्ति है ।

गया।
राजनीतिक परिवर्तन के कारण लंबे समय के बाद भारत फिर से खुद को खोज रहा है। अपनी जड़ों की तरफ वापसी करना चाहता है। जिसे विचारों की घर वापसी कहकर संबोधित किया गया। जरूरी है कि भारत प्रेमी बौद्धिक वर्ग सत्य के सूर्य की स्थापना करने के लिए अध्यवसाय में जुट जाए। सिर्फ भावनात्मक प्रवर्चनों, कार्यक्रमों से आगे बढ़कर भ्रमों के निवारण का जतन करे। ऐसे कुशल बौद्धिक योद्धा ही अपनी ज्ञान परंपरा को सामने लाकर तथ्य, प्रमाणों के साथ उनकी युगानुकूल व्याख्या करेंगे। इसके लिए हमें लोकसंग्रही और विनम्र बनना पहली शर्त है। परंपरा,जीवन पद्धति और

समझने तथा भारत का मौलिक चिंतन स्थापित करने में मदद मिलती है। इससे ही गुलत बातों का खंडन करते हुए हम सही विमर्श की स्थापना में सफल हो पाएंगे।
भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों के आधार पर संपूर्ण विश्व के लिए हमें ही वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व देना होगा। जिसकी एक झलक हमें स्वामी विवेकानंद में दिखती है। ऐसे में 'स्वबोध' का जागरण ही विकल्प है। पहले हमारे अपने विचार को भारत तो स्वीकार करे। वह आत्मदैन्य से मुक्त होकर भारत को भारत (ईंडिया नहीं) की नजर से देखना प्रारंभ करे। वैचारिक साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए कई स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसे इस तरह से समझिए कि गौरा



परिवार पर छाप संकटों के बीच ये प्रयत्न ही हमें आत्मशक्ति देंगे। दुनिया भर में चल रहे सभ्यतागत संघर्ष के बीच भारत को अपनी वृहत्तर भूमिका का निर्वहन करना है, क्योंकि हमारे पास दुनिया को देने के लिए समावेशी विचार है। जहां साझापन सौंदर्य की तरह है, विविधता और बहुलता का यहां उत्सव मनाया जाता है। हम पूजा में भी अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। बहुलतावादी समाज होने कारण हमने मतभिन्नता का सदैव स्वागत किया। इसका उदाहरण हमारी शास्त्रार्थ परंपरा है। इसलिए एक किताब,एक विचार, एक देवता को मानने और दूसरे विचार को समाप्त करने को आतुर विचार भारत को नहीं समझ सकते। जहां दुनिया के हर पंथ के लोग नैसर्गिक सहजता से सांस ले सकते हैं। यहां कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है। सब समान रूप से इस धरती मां की संतान हैं। ऐसे में भारत केंद्रित विमर्श ही विश्व शांति का मार्ग है। स्वत्व ही मार्ग है, जिस पर चलने के लिए हमें महात्मा गांधी, धर्मपाल, सीताराम गोयल, दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र का अध्ययन मदद कर सकता है। इससे भारत के मूल विचार की

बनाना और अंग्रेजी सिखाना आज भी हिंदुस्तान में दो सबसे बड़े व्यापार हैं। यही उपनिवेशवादी मानसिकता है। इसके चलते ही हमारे गांव उड़ते चले गए और संयुक्त परिवार बिखर गए। आज एकल परिवारों के नाते अलग तरह के सामाजिक-सांस्कृतिक संकट हमारे सामने हैं। जाति, भाषा, क्षेत्र,पंथ की लड़ाइयों को छोड़कर भी बहुत सी विभाजनकारी बातें हर दिन आज भी खोजी जाती हैं , फिर आख्यान (नरैटिव) गढ़े जाते हैं। भारत जिसे कभी ईंडिया बनाने की कोशिश हुई, उसे भारत बनाए रखने के लिए हमें ही आगे आना होगा। क्योंकि भारत का नष्ट होना, उस विचार का मिट जाना होगा, जिसने हमें वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश दिया। जिसने हमें राम, कृष्ण,शिव, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जैसे नायक दिए। जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः में अपनी मुक्ति देखी और लोक-मंगल जिसका मूलमंत्र रहा।(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभागे के अध्यक्ष हैं।)

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

जब एक चुप्पी टाल सकती है बड़ा विवाद, गुस्से में बोलने से बेहतर है कुछ देर का मौन

(रितुप्रिया शर्मा)
चुप रहकर अपने आप को प्रदर्शित करने की कला को मौन के रूप में भी देखा जाता है। कई बार चुप रहकर भी हम बहुत सारी बातें कह देते हैं, जो हम बोलकर भी नहीं कह पाते। ऐसा इसलिए नहीं है कि बोलना अच्छ नहीं है, बल्कि मौन एक कला और साधना है, जिससे हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शब्द नहीं, बल्कि आत्मा बोलती है।

आज भाग-दौड़, शोर-शराबे का युग है, जिसमें ज्यादातर सिर्फ व्यर्थ की आपाधापी है और प्रतियर्धा से जुड़ते लोग हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों का बोलना अनवरत जारी रहता है। ऐसी परिस्थिति में मानसिक शांति कैसे मिल पाएगी, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। मौन एक प्राकृतिक शक्ति है और बुद्धिमानी की निशानी भी है, क्योंकि हर बार बोलकर अपने आपको प्रकट करना आवश्यक नहीं है। बेहिसाब और बेलगाम शब्द कई बार मुश्किल खड़ी कर देते हैं, लेकिन मौन व्यक्ति को आमतौर पर विचारशील बनाता है। चुप रहकर हम एक साधना करते हैं, जो हमें अपने भीतर जानने का अवसर प्रदान करती है और स्वयं का मूल्यांकन आसानी से हो पाता है। संत-महत्मा भी अपने जीवन में मौन की साधना के जरिए ही अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में सामने आए थे। हालांकि खुद को अभिव्यक्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम कहां और किससे संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मौन की भाषा को समझने वाले उचित व्यक्ति की भी जरूरत होती है। यानी कहा जा सकता है कि मौन अभिव्यक्ति का एक बेहतर जरिया है, लेकिन इसके लिए देशकाल के तकाजे को ध्यान में रखना जरूरी होता है।

बहरहाल, मानसिक शांति मौन का सबसे प्रबल लाभ है। निरंतर चलने वाले संवाद ने व्यक्ति को अनावश्यक विवादों के दौर में डाल दिया है और ये अनावश्यक विवाद आमतौर पर व्यक्ति के शब्दों से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे में जरूरत भर मौन का रास्ता अपनाकर हम ऐसी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हमारी विचार शक्ति और चेतना का जागरण मौन के द्वारा ही संभव है और मौन रहकर हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने में समर्थ बन सकते हैं।

अगर हम अपना व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं, तो हमें अपने शब्दों को सोच-समझकर बोलना होगा और अनावश्यक बातों से बचना होगा। समाज में सम्मान पाने के लिए भी मौन एक जरूरी आवश्यकता है। इस अनुभव से ज्यादातर लोग गुजरे होंगे, जिसमें समाज व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुनता है, जो अनावश्यक बोलने से बचता है। मौन रहने का एक फायदा और है कि हम अच्छे श्रोता

बनते हैं और दूसरे के विचारों का आदर करना भी सीखते हैं।

सबसे अहम पक्ष यह है कि क्रोध के समय मौन ही हमें निरंतर होने वाली आलोचना और स्वास्थ्य की हानि से बचाता है। इसके अलावा, रिश्तों को भी बचाने में मौन की भूमिका स्वयंसीद्ध रही है। यह आम अनुभव रहा है कि अगर किसी ने कोई कठोर शब्द बोल दिया, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और उसका असर संबंधों तक पर पड़ता है। दोस्ती से लेकर भाईचारे या फिर दंपतियों तक के रिश्ते टूट जाते हैं या कम से कम लंबे जहोजहद में चले जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना ठीक है, लेकिन भावनाओं की तीव्रता हो, तब मौन रहना बेहद आवश्यक हो जाता है। बड़े-बुजुर्ग भी कहते हैं कि चुप रहना बुद्धिमानी का संकेत है। अगर हम क्रोध के समय चुप रह गए, तो इसका लाभ हमें तत्काल भी दिख सकता है। प्रतिक्रिया देना लाजिमी है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बाद में भी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। मौन का आध्यात्मिक महत्त्व जगजाहिर रहा है। योग, ध्यान और साधना में व्यक्ति मौन को ही अपनी विशेष स्थिति के रूप में अपनाता है और अपने आसपास के माहौल को भी सुंदर बनाता है। मौन रहने से हम अपने भीतर की आवाज को अच्छे से सुन पाते हैं और यही आत्मज्ञान और आत्मविश्वास हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि मौन के नाम पर हम हर परिस्थिति और हर अत्याचार को चुप रहकर सहते रहें। न्याय की रक्षा के लिए हमें चीजों को ध्विेक से तोलना होगा और सही समय आने पर सही बात को बोलना होगा। जीवन के पथ पर हमें मौन का कितना प्रयोग करना है, यह पूरी तरह हमारी परिस्थितियों पर निर्भर है।

आज की तकनीकी दुनिया और इसकी प्रणाली ने लोगों को हर वक्त संवाद में व्यस्त कर दिया है। चुप रहने का कोई मौका नहीं है और जो व्यक्ति निरंतर इस तरह से अपने आप को खर्च करता रहता है, उसके पास भीतर की ऊर्जा शेष नहीं रहती। इसलिए स्वयं को मौन से जोड़ना एक बेहतर जीवनशैली का अच्छा साधन है। अपने विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हुए वास्तविक उद्देश्य को ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि मौन एक अनुशासन है और हमारे धैर्य की परीक्षा है।

जीवन को संतुलित बनाने और विकास के लिए मौन का महत्त्व अद्वितीय है। जो बात बहुत से शब्द नहीं कह सकते, वह एक चुप्पी कह सकती है। यही मौन आगे चलकर हमें अध्यास में परिवर्तित करना चाहिए, ताकि यह हमें बेहतर जीवन की ओर लेकर जाए। मौन एक संतुलित जीवनशैली का नाम है और इसे अपनाकर हम अपना विकास ही करेगे।

कोलकाता की दुर्गा पूजा में भगदड़- कहां चूका भीड़ प्रबंधन का मॉडल?

हालिया प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक पसंद-नापसंद के आधार पर हुई तैनातियों के कारण कई ऐसे अधिकारी दुर्गा पूजा की व्यवस्था के दायरे से किनारे हो गए। नए कमान तंत्र में वह प्रशासनिक साहस और स्वायत्तता नहीं दिखी, जो ज़मीन पर अचानक उमरी स्थिति को देखकर कड़े फैसले ले सके। निर्णय लेने में हुई हिचकिचाहट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। यदि कोलकाता को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, वैश्विक प्रतिष्ठा और यूनेस्को की विरासत को अक्षुण्ण रखना है, तो इस त्रासदी को केवल एक औपचारिक जांच आयोग की फाड़लों में दबाया नहीं जा सकता।

(राहुल लाल)
कोलकाता का 'भीड़ प्रबंधन मॉडल' एक ऐसा मानक माना जाता था, जहां लाखों की संख्या में लोग संकरी गलियों से होकर गुजरते थे, भव्य पंडालों में देवी की प्रतिमाओं के दर्शन करते थे और बिना किसी अग्रिय घटना के अपने घरों को लौट जाते थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या मौसमी पर्व नहीं है, बल्कि यह यूनेस्को की ओर से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकृत एक विशाल महोत्सव है। शरद ऋतु की षष्ठी से लेकर विजयादशमी तक बड़ी संख्या में लोग जब एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो इसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कुंभ, हाथरस, नैना देवी अथवा सबरीमाला जैसे धार्मिक आयोजनों में होने वाली भगदड़ और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं जब भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती थीं, तब पश्चिम बंगाल और विशेष रूप से कोलकाता पुलिस की मिसाल गर्व से दी जाती थी। कोलकाता का 'भीड़ प्रबंधन मॉडल' एक ऐसा मानक माना जाता था, जहां लाखों की संख्या में लोग संकरी गलियों से होकर गुजरते थे, भव्य पंडालों में देवी की प्रतिमाओं के दर्शन करते थे और बिना किसी अग्रिय घटना के अपने घरों को लौट जाते थे। मगर 17 अक्टूबर की शाम उत्तरी कोलकाता के चोरबागाना सार्वजनिक पूजा पंडाल में जो घटा, उसने इस ऐतिहासिक गौरव, प्रशासनिक साख और उत्सव की मर्यादा पर एक गहरा आघात किया है। महासम्मेली की शाम भारी बारिश और उसके बाद हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई।



इस घटना को लेकर अब तक की जांच में सामने आया है कि यह केवल एक अप्रत्याशित प्राकृतिक विपदा नहीं थी, बल्कि इसमें पंडाल आयोजकों की सरचनात्मक अनदेखी, प्रशासनिक संवेदनहीनता, वीआईपी संस्कृति और दशकों से सिंचित संस्थागत प्रोटोकॉल के टूटने की कई कड़ियां शामिल हैं। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, प्रशासनिक तंत्र सबसे पहले प्रकृति को खल बनाता है, जैसे-अचानक भारी बारिश आ गई और बिजली गुल हो गई। मगर तथ्य इस बहानेबाजी को फिरे से खारिज करते हैं। कोलकाता में अक्टूबर के महीने में चक्रवाती दबाव के कारण भारी बारिश कोई नई परिघटना नहीं है। फिल्ले वर्ष भी भारी वर्षा और जलभरवख के बीच पूजा निर्बाध संपन्न हो थी। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ में

कई निर्दोष लोगों की जान चली गई? इस घटना की जांच ने प्रशासनिक दावों के उलट भयावह सच्चाई को उजागर किया है। वहां लगे सीसीटीवी की तस्वीरों से पता चलता है कि बारिश शुरू होते ही जब बाहर खड़े हजारों लोग छत की तलाश में भागे, तो संकरे निकासमार्ग पर बनी कमजोर अस्थायी सीढ़ियां भारी दबाव में ढह गईं। सीढ़ियों के टूटने ही आगे चल रहे लोग गिर पड़े और मुख्य निकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर लगातार बजती सीटियां और लाउडस्पीकर पर हुई अनियंत्रित घोषणाओं से लोगों में दहशत फैल गई और इसके तुरंत बाद बिजली भी गुल हो गई।

घने अंधेरे में लोग एक-दूसरे को कुचलते हुए इधर-उधर भागते रहे। ऐसे में इस त्रासदी को प्राकृतिक नहीं, बल्कि समय पर भीड़ को

नियंत्रित न कर पाने की प्रशासनिक विफलता का परिणाम माना जा रहा है। नियमों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक पंडाल में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी पहले से होना अनिवार्य है, मगर जांच में सामने आया है कि चोरबागाना हादसे के दौरान बिजली की तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। इस पूरी त्रासदी का निराशाजनक पहलू यह है कि कोलकाता पुलिस और प्रशासन के पास इस तरह की समस्या से निपटने का पहले से आजमाया हुआ मॉडल मौजूद था, फिर भी भगदड़ को नहीं रोका जा सका। वर्ष 2015 का उदाहरण अभी भी इस शहर की स्मृति में ताजा है। तब दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क में 'विश्व की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा' स्थापित की गई थी। तृतीया और चतुर्थी के दिन ही लाखों लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। जब पुलिस ने देखा कि भीड़ की सघनता सुरक्षा मानकों को पार कर गई है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, तो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने एक साहसिक निर्णय लिया। प्रशासन ने किसी राजनीतिक दबाव, आयोजकों के रसूख या जनता की नाराजगी की परवाह किए बिना उस पंडाल को पूरे उत्सव के लिए तत्काल सील कर दिया था। उस सख्त फैसले ने एक संभावित महा-त्रासदी को टाल दिया था। इसके बाद के वर्षों में भी जब कभी श्रौभीष्म या कल्याणी जैसे पंडालों में भीड़ अनियंत्रित हुई, तो पुलिस ने तुरंत लेजर शो बंद करवाए, प्रवेश द्वारों पर अवरोधक लगाए और भीड़ के प्रवाह को कई किलोमीटर पहले ही नियंत्रित कर दिया।

दुर्गा पूजा पर कोलकाता पुलिस का भीड़

प्रबंधन मॉडल किसी कागजी नियमों से अधिक उन अनुभवी अधिकारियों के व्यावहारिक ज्ञान पर निर्भर करता था, जो उत्तर और दक्षिण कोलकाता के एक-एक नुकाड़, गली और मोड़ से वाकफ थे। हालिया प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक पसंद-नापसंद के आधार पर हुई तैनातियों के कारण कई ऐसे अधिकारी दुर्गा पूजा की व्यवस्था के दायरे से किनारे हो गए। नए कमान तंत्र में वह प्रशासनिक साहस और स्वायत्तता नहीं दिखी, जो जमीन पर अचानक उभरी स्थिति को देखकर कड़े फैसले ले सके। निर्णय लेने में हुई हिचकिचाहट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। यदि कोलकाता को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, वैश्विक प्रतिष्ठा और यूनेस्को की विरासत को अक्षुण्ण रखना है, तो इस त्रासदी को केवल एक औपचारिक जांच आयोग की फाड़लों में दबाया नहीं जा सकता। आने वाले वर्षों के लिए एक कड़ा, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी 'दुर्गा पूजा सुरक्षा घोषणापत्र' लागू करना जरूरी है। प्रत्येक पूजा पंडाल के आंतरिक क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग और निकास चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय भवन संहिता और एनडीएमए मानकों के तहत उसकी अधिकतम सुरक्षित क्षमता निर्धारित की जानी चाहिए। यदि किसी पंडाल की सुरक्षित क्षमता 800 व्यक्तियों की है, तो 801वें व्यक्ति का प्रवेश रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी पंडाल का निकास द्वार उसके प्रवेश द्वार से कम से कम डेढ़ गुना अधिक चौड़ा होना चाहिए। संकरी गलियों में खुलने वाले निकास द्वारों वाले स्थलों पर पंडाल लगाने की अनुमति प्रतिबंधित करनी होगी।

पाँच व्यक्तियों को मानद उपाधि, 11 शिक्षण संस्थानों एवं सेंटर संचालकों का सम्मान

पारस संगम 2026 में प्रतिभाओं का सम्मान, 101 शिक्षकों को मिला गौरव

● झरना यादव की पढ़ाई के लिए 5,100 की सहायता, विद्यार्थियों के लिए वेलकम एवं फ़ेयरवेल समारोह

रायपुर। पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में 24 अक्टूबर 2026 को शहीद स्मारक भवन, घड़ी चौक, रायपुर में ‘पारस संगम 2026-एक्सीलेंस अवॉर्ड’ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा, समाजसेवा, उद्यमिता, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सेवा, युवा नेतृत्व, साहित्य, कला एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 101 शिक्षकों, 11 स्कूलों, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों तथा पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के



सेंटर संचालकों को सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हुआ सम्मान समारोह समारोह में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी, बाल आयोग की अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त डॉ. वंदिका शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा तथा केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग से संबंधित प्रतिनिधि शिव पात्रे सहित विभिन्न क्षेत्रों के अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा सकीला खान, प्रीति रानी तिवारी, उमा कुशवाहा तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। पाँच व्यक्तियों को मानद उपाधि से किया गया सम्मानित

कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा उनके योगदान को व्यापक पहचान दिलाना रहा। सम्मान समारोह के साथ विद्यार्थियों के स्वागत एवं विदाई कार्यक्रम ने आयोजन को अर्वाँद दिया गया। डॉ. उदयभान सिंह चौहान को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’, तपस्वीनी सदावती को ‘एक्सीलेंस स्कूल अवॉर्ड’ तथा डॉ. शेख मोहम्मद उस्मान को ‘इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। राम तिवारी को उनके प्रेरणादायी योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. प्रीति उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रोफेसर डॉ. रात्रि लहरी को भी सम्मानित किया गया। डीबी ग्राफिक को व्यावसायिक उद्यमिता, अधिन कुमार को ‘हमर छत्तीसगढ़’ फिल्म प्रोडक्शन तथा वेव्स को फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया गया। सुभाष चंद्र बोरके को ‘पारस विधि साहित्य गौरव सम्मान’ से नवाजा गया।

समारोह में एस. के. शर्मा, ब्रजभूषण यादव, प्रिया गुप्ता, चंद्रप्रकाश नौरव एवं रुद्रवीर सोनी को उनके योगदान के लिए ‘एक्सीलेंस स्कूल अवॉर्ड’ तथा डॉ. शेख मोहम्मद उस्मान को ‘इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। राम तिवारी को उनके प्रेरणादायी योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. प्रीति उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रोफेसर डॉ. रात्रि लहरी को भी सम्मानित किया गया। डीबी ग्राफिक को व्यावसायिक उद्यमिता, अधिन कुमार को ‘हमर छत्तीसगढ़’ फिल्म प्रोडक्शन तथा वेव्स को फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया गया। सुभाष चंद्र बोरके को ‘पारस विधि साहित्य गौरव सम्मान’ से नवाजा गया।

विशेष स्वरूप प्रदान किया। अर्वाँद दिया गया। डॉ. उदयभान सिंह चौहान को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’, तपस्वीनी सदावती को ‘एक्सीलेंस स्कूल अवॉर्ड’ तथा डॉ. शेख मोहम्मद उस्मान को ‘इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। राम तिवारी को उनके प्रेरणादायी योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. प्रीति उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रोफेसर डॉ. रात्रि लहरी को भी सम्मानित किया गया। डीबी ग्राफिक को व्यावसायिक उद्यमिता, अधिन कुमार को ‘हमर छत्तीसगढ़’ फिल्म प्रोडक्शन तथा वेव्स को फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया गया। सुभाष चंद्र बोरके को ‘पारस विधि साहित्य गौरव सम्मान’ से नवाजा गया।

झरना यादव की पढ़ाई के लिए 5,100 की सहायता शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की ओर से झरना यादव को उनकी पढ़ाई के लिए 5,100 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस पहल के माध्यम से फाउंडेशन ने प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। सहयोगी संस्थाओं एवं व्यापार जगत की रही सहभागिता आयोजन को सफल बनाने में विभिन्न संस्थानों एवं सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें रुद्रास बीड्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक गीता वर्मा, सम्राट कॉर्पोरेशन रायपुर के डायरेक्टर मोहन वल्लानी, आवेश कंप्यूटेक आईटी सॉल्यूशन के संस्थापक अजय साहू, महती स्टूडियो के संचालक संजय महतो, डी. पी. गोस्वामी, अर्निताका भारद्वाज तथा द मदर्स इंडीग्रल एजुकेशन से तपस्वीनी सदावती का सहयोग शामिल रहा। छत्तीसगढ़ व्यापारी संघ के अध्यक्ष शेखर वर्मा एवं संघ के सदस्यों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।

फाउंडेशन एवं संस्थान की टीम ने संभाली व्यवस्थाएँ कार्यक्रम में पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं फाउंडर प्रेसिडेंट डॉ. कविता कुम्भज, सचिव मूलचंद कश्यप तथा कोषाध्यक्ष राहुल कुम्भज उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ज्योति कुम्भज सहित फाउंडेशन एवं पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से जुड़े सदस्यों ने कार्यक्रम के संचालन और व्यवस्थाओं में सहभागिता की। इस अवसर पर आर. एन. भारद्वाज, रितु सिन्हा, अमृता तथा संस्थान की टीम से रानी, काजल,

दीपिका, कृष्णा, प्रतीक, पायल, राधिका, नमन, आशीष, धनेश एवं मिलन सहित अनेक अतिथि और सहयोगी उपस्थित रहे। वेलकम एवं फ़ेयरवेल समारोह में विद्यार्थियों को मिले खिताब कार्यक्रम के दूसरे चरण में पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए वेलकम एवं फ़ेयरवेल समारोह आयोजित किया गया। इसमें नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया तथा वरिष्ठ विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। फ़ेअर्स समारोह में केसरी को ‘मिस फ़ेअर’ का खिताब दिया गया। भाटागांव शाखा से प्रवीण को ‘मिस्टर फ़ेअर’ तथा तनु को ‘मिस फ़ेअर’ चुना गया। वहीं फ़ेयरवेल समारोह में मनीष को ‘मिस्टर फ़ेयरवेल’ तथा योग्यता को ‘मिस फ़ेयरवेल’ का खिताब प्रदान किया गया।

शिक्षा, समाजसेवा और प्रतिभा प्रोत्साहन का साझा मंच पारस संगम 2026 ने शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और विद्यार्थियों को एक साझा मंच प्रदान किया। सम्मान समारोह के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पहचान मिली, वहीं वेलकम एवं फ़ेयरवेल कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में उत्साह का संचार किया। आयोजन के माध्यम से पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन ने शिक्षा, समाजसेवा और प्रतिभा प्रोत्साहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समाजहित में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं का सम्मान और विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग इस समारोह का प्रमुख संदेश रहा।

जिले में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे 234 बोरवेल रिचार्ज सैंड फिल्टर पिट

विकसित भारत-जी राम जी के तहत 1.32 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत

● जल संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार, 180 से अधिक ग्राम पंचायतों में हो रहा निर्माण



दी गई है। इन संरचनाओं के निर्माण से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देकर जल संकट की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में

जिले में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न

संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। बोरवेल रिचार्ज सैंड फिल्टर पिट ऐसी संरचना है, जिसके माध्यम से वर्षा जल को रेत एवं अन्य फिल्टर सामग्री की सहायता से छानकर जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है।

पांचों विकासखंडों में हो रहा निर्माण

जिले की 180 से अधिक ग्राम पंचायतों में मांग एवं आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक बोरवेल रिचार्ज सैंड फिल्टर पिट का निर्माण कराया जा रहा है। विकासखंडवार स्थिति के अनुसार करतला में 64, कोटघोरा में 30, कोरबा में 66, पाली में 13 तथा पोड़ी उपरोड़ा में 61 रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। इन संरचनाओं से विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जहां जलस्तर में गिरावट की समस्या है। वर्षा जल को बेहतर उपयोग होने से जल उपलब्धता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। विकसित भारत-जी राम जी से जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के इन प्रयासों के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ जल सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके।

महतारी वंदन योजना बनी वैसाखी बाई का सहारा, छोटी-छोटी जरूरतों से संवर रहा परिवार का भविष्य

गौरैया पेंड्रा मरवाही। परिवार की खुशहाली केवल बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों के समय पर पूरा होने से भी आती है। छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में इसी तरह सकारात्मक बदलाव ला रही है। गौरैया विकासखंड की ग्राम पंचायत धनौली के दाढ़ीपारा निवासी वैसाखी बाई के लिए यह योजना धरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने बच्चे की पढ़ाई में सहयोग देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त की राशि प्राप्त होने से वैसाखी बाई को आर्थिक संबल मिला है। वे इस राशि का उपयोग अपने लिए साग-सब्जी खरीदने तथा अपने बच्चे की पढ़ाई पर होने वाले खर्च में करती हैं। उनके लिए योजना की यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने और बच्चे की शिक्षा में योगदान देने



का अवसर भी है। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं और बच्चों की पढ़ाई के खर्च का ध्यान रखना आसान नहीं होता। ऐसे में नियमित आर्थिक सहायता उन्हें अपने छोटे-छोटे फैसले स्वयं लेने और परिवार की जरूरतों में सहयोग करने का भरोसा देती है। वैसाखी बाई की कहानी इसी भरोसे और आत्मनिर्भरता की एक सहज मिसाल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही परिवार के पोषण और बच्चों की शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों में सहयोग दे रही है।

चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से वर्षा की संभावना को देखते हुए सभी विभाग अलर्ट मोड में रहें:

स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली बहाली के लिए दिए निर्देश कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की

● निचले इलाकों की निगरानी, राहत शिविरों की तैयारी..



सामुदायिक भवनों में तैयार होंगे राहत शिविर

जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से राहत शिविरों के लिए स्थल चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक भवनों को प्राथमिकता देते हुए वहां पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा और रोगाणी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि राहत शिविरों के लिए स्कूलों का चयन न किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को जरूरत पड़ने पर कई दिनों तक सुरक्षित आश्रय मिल सके। ग्राम पंचायतों को टॉर्च, रस्सी और अन्य जरूरी सामग्री तैयार रखने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों और एसडीआरएफ से प्राप्त आवश्यक उपकरणों को भी तैयार रखा जाएगा। बचाव कार्यों के लिए गोताखोरों की टीम को तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 28 और 29 अक्टूबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सकीय अम्ल, दवाइयों और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूरस्थ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों में जिन गर्भवती महिलाओं का प्रवास संभावित है, उन्हें पूर्व सूचना देकर 27 अक्टूबर को ही स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराने की व्यवस्था की जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्वास्थ्य संस्थानों में जांचेबल टॉर्च, बैटरी चालित लाइट और अन्य दैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था रखी जाएगी। मितानियों के पास दवाई पैटी और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए सभी विभाग समन्वय से काम करें। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए अधिकारी और उनकी टीमों फोन चालू रखें तथा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को तैयार रखें। उन्होंने लोगों से भी मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने, जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों पर अमल करने की अपील की। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को कोटवारा के माध्यम से गांवों में मुनादी कराकर लोगों को वर्षा, तेज हवा और संभावित जलभराव के प्रति सतर्क करने के निर्देश दिए। निचले और जोखिमयुक्त क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने तथा जलस्तर बढ़ने की आशंका होने पर वहां के लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी करने को कहा गया।

प्रशासन का प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को बाढ़ या

बिजली लाइनों का निरीक्षण और बहाली के लिए टीमें तैयार सीएसपीडीसीएल को बिजली लाइनों का पूर्व निरीक्षण कराने और जिन पेड़ों की डालियों से लाइनें प्रभावित होने की आशंका है, उनकी कटौत कराने के निर्देश दिए गए हैं। लाइनें, ट्रांसफॉर्मर और मरम्मत संबंधी संसाधनों को तैयार रखा जाएगा। जिले के सभी पांच विद्युत आपूर्ति डिवीजन को अलर्ट रहने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर स्थिति की सूचना लगातार देने को कहा गया है। 128 और 29 अक्टूबर को शहरी, ग्रामीण तथा कटघोरा ग्रामीण डिवीजन से प्रभावित गांवों और मोहल्लों की सूची प्रतिदिन शाम 5 बजे तक उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने तक प्रभावित क्षेत्रों की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।

पेड़ गिरने या पानी भरने पर रास्ते तत्काल खुलवाए जाएंगे नगरीय निकालों को आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेड़ गिरने, सड़क अवरुद्ध होने, अंडरब्रिज में पानी भरने या सड़कों पर जलभराव होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर आगमन बहाल कराया जाएगा। इसके लिए कटर, परिवहन साधन और आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, वन विभाग और थाना प्रभारियों को सड़कें खुलवाने के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा गया है।

आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष से करें संपर्क जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आपात स्थिति में नागरिक दूरभाष नंबर 7759228548 पर संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भी आवश्यकतानुसार संपर्क नंबर जारी किए जाएंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष से समन्वय बनाए रखने तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दुदावत ने नागरिकों से अपील की है कि मौसम विभाग और जिला प्रशासन की चेतावनियों पर ध्यान दें, नदी-नालों और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष या स्थानीय प्रशासन को दें।

बिलाईगढ़ जनपद सीईओ ने सलिहा और धौराभाठा में किया स्थल निरीक्षण, हितग्राहियों से की चर्चा

प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवस एक माह में पूर्ण कराने के निर्देश

● सलिहा में 378 स्वीकृत आवसों में से 309 पूर्ण, शेष 69 आवसों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश



सीईओ ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में अपूर्ण आवसों के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में जनपद

पंचायत बिलाईगढ़ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश्वरी बर्मन ने ग्राम पंचायत सलिहा एवं धौराभाठा (सु) का दौरा कर निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवसों का

स्थल निरीक्षण किया तथा हितग्राहियों को एक माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ बर्मन ने आवस हितग्राहियों

के घर पहुंचकर निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर हितग्राहियों से चर्चा की तथा आवस निर्माण में हो रही देरी के कारणों और कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हितग्राही एवं संबंधित विभागीय अमला आपसी समन्वय से निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।

सलिहा में 69 अपूर्ण आवसों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर

ग्राम पंचायत सलिहा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 378 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 309 आवसों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 69 आवास अपूर्ण हैं। जनपद सीईओ ने इन आवसों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित हितग्राहियों को एक माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास योजना से जुड़े अमलों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा आवश्यक समन्वय के माध्यम से अपूर्ण आवसों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। बर्मन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। ऐसे में स्वीकृत आवसों के निर्माण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में आवस निर्माण पूर्ण नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार राशि वसूली की कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के विकासखंड समन्वयक विद्यासागर साहू एवं तकनीकी सहायक लक्ष्मण महिलागे उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंचगण एवं आवास हितग्राही भी मौजूद थे। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए सभी अपूर्ण आवसों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त समाचार

सहकारी समितियों के परिसमापन के पूर्व मंगाई गई दावा आपति

बिलासपुर। कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा जिले की सहकारी समितियों के परिसमापन के पूर्व 60 दिन के भीतर दावा-आपति मंगाये गये है। परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक ने बताया कि जिले की प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कारीछपर, ठरकपुर, कैमाडीह, बरगन, सार्वतपुर, सोंटी, उपका, लुक्क, खैरा एवं अम्बेडकर प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार सह. समिति मर्या. अम्बेडकर नगर के परिसमापन को कार्यवाही हेतु समिति के दावेदार, लेनदार अपने दावेमय लिखित प्रमाण में 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड, संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

12वीं राज्य स्तरीय ताइक्रांडो प्रतियोगिता में रायगढ़ बना ओवरऑल चैंपियन, बिलासपुर को मिला दूसरा स्थान

बिलासपुर। खेलो ताइक्रांडो यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा 12वीं राज्य स्तरीय ताइक्रांडो प्रतियोगिता का दो दिवसीय भव्य आयोजन अभिलाषा परिसर, तिफ्फा बिलासपुर में किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से लगभग 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के एसपी परमेश्वर तिलकवार उपस्थित रहे। इस अवसर पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजीव साहू एवं मनोज जायसवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ विभिन्न मुकाबलों में भाग लिया। प्रतियोगिता में रायगढ़ जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, बिलासपुर जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सरगुजा तीसरे, बालोद चौथे, दुर्ग पांचवें, मुंगेली छठवें, गैरैला-पेंड्रा-मरवाही सातवें और कबीरधाम जिले ने आठवें स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी चयनित खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की ताइक्रांडो प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। आगामी 29, 30 और 31 दिसंबर 2026 को बिलासपुर में चौथी बार राष्ट्रीय स्तर की ताइक्रांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता इंटरनेशनल मास्टर गणेश सागर होंगे।

युवा रत्न सम्मान : 30 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन

बिलासपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं और स्वीच्छिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा रत्न सम्मान वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सम्मान के लिए 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, साहसिक, शैक्षणिक, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को शामिल किया गया है। आवेदन जमा करने की तिथि 30 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। योजना की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं मार्गदर्शिका विभाग की वेबसाइट [h4p2h42.पू.दृग1.दुठु](#) से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत एक स्वीच्छिक संगठन तथा 14 विभिन्न क्षेत्रों में एक-एक उत्कृष्ट युवा का चयन किया जाएगा। चयनित स्वीच्छिक संगठन को पदक, शॉल, प्रशस्ति पत्र सहित 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य के लिए चयनित युवा को 2.50 लाख रुपए तथा अन्य 13 क्षेत्रों में चयनित युवाओं को प्रत्येक 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ पदक, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आवेदन सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, स्व. बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, बहतराई, जिला-बिलासपुर के कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे।

सड़क सुरक्षा पर सख्ती, 10 माह में 892 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जनवरी से अक्टूबर माह तक 892 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने स्पष्ट किया कि निलंबित लाइसेंस के बावजूद वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सड़क सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि पंथी मोड़ पर सीमेंट कांक्रोट से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है।

समान नागरिक संहिता के प्रास्वरूप में जनभागीदारी बने बिलासपुर में आठ जिलों के प्रतिनिधियों ने रखे सुझाव

■ महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मिलेगी मजबूती, धार्मिक आस्थाओं और पूजा-पद्धतियों में नहीं होगा हस्तक्षेप : श्री शत्रुघ्न

■ संभाग स्तरीय परामर्श बैठक में विभिन्न विषयों पर खुलकर हुई चर्चा, 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन भी दे सकेंगे सुझाव

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का प्राारूप तैयार करने की प्रक्रिया में नागरिकों और विभिन्न संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए

आज बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई। देवकी नंदन दीक्षित सभागृह, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित बैठक में आठ जिलों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह और श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह, रायपुर संभागायुक्त एवं समिति के सचिव श्री श्याम धावड़े तथा बिलासपुर संभागायुक्त श्री



सुनील जैन उपस्थित थे। समिति के सदस्य श्री शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पारिवारिक विषयों से संबंधित दो दर्जन से अधिक कानून एवं प्रावधान प्रचलित हैं, जिनमें अनेक भिन्नताएं हैं। समान नागरिक संहिता पर विचार का उद्देश्य इन विषयों में समानता को बढ़ावा देना तथा

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को अधिक सुदृढ़ बनाना है। श्री सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए कहा कि संहिता न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी भी धर्म की पूजा-पद्धति, धार्मिक आस्था और रीति-रिवाजों

कलेक्टर-एसएसपी ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

बिजली,पेयजल और पेंशन से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे लोग

■ संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में लोगों ने निजी एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर निराकरण की मांग की। कलेक्टर एवं एसएसपी ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने भी लोगों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में ग्राम पंचायत निरतू के सरपंच ने कलेक्टर को

जापन सौंपकर बताया कि ग्राम पंचायत निरतू एवं उसके आश्रित ग्राम अदराली में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी टंकी से अब तक पेयजल वितरण शुरू नहीं हुआ है। पानी टंकी बनने के बावजूद ग्रामीणों को नियमित पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शीघ्र पेयजल आपूर्ति शुरू कराने की मांग की। साथ ही निरतू के खाल्हेपारा में स्थापित ट्रांसफॉर्मर बंद होने की समस्या से अवगत कराया। संबंधित मोहल्लों में लगभग 180 परिवार निवासरत हैं, जिन्हें पर्याप्त बिजली व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली के खंभे लगाकर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने का आग्रह किया। तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम चनाडोंगरी निवासी भोला कैवर्त ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी माता के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। माता की मृत्यु के बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने



और आवास निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता होने के बावजूद अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने मामले की जांच कर आवास निर्माण की राशि दिलाने का अनुरोध किया। वहीं तिफ्फा निवासी कैलाश बाई ध्व ने अपने पुत्र का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की समस्या से अवगत कराते हुए प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानी दूर करने की मांग की।

बोदरी तहसील के ग्राम मुढ़ीपार के किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि उन्होंने रबी फसल के लिए एचडीएफसी बीमा कंपनी के माध्यम से फसल का बीमा कराया था, लेकिन अब तक उन्हें बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बीमा राशि दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

बाढ़ आपदा से निपटने तैयार हो रही जल मित्रों की टीम,57 लोगों को विशेष प्रशिक्षण

■ डूबते लोगों को बचाने से लेकर मोटर बोट संचालन तक सिखाए जा रहे बचाव के गुर

बिलासपुर। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनहानि रोकने और त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर जल मित्रों की टीम तैयार की जा रही है। इसके लिए जिले के विभिन्न अनुभागों एवं तहसीलों से चयनित 57 कोटवारों, मल्लुआरों, गोताखोरों और कुशल तैराकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा की स्थिति में स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षित लोगों की मदद से तत्काल बचाव कार्य शुरू करना और जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाना है।



अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं एवं एसडीआरएफ प्रशिक्षण केंद्र, परसदा में 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बाढ़ से बचाव की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मोटर बोट (ओबीएम) के संचालन, पानी में डूबते लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, तैराकी की विभिन्न तकनीकों तथा लाइफ जैकेट और लाइफ ब्वॉय के सही उपयोग की

जानकारी दी जा रही है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों और सामग्रियों से भी प्रशिक्षणार्थियों को परिचित कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से जिले में ऐसे जल मित्रों की टीम विकसित की जा रही है, जो बाढ़ एवं जलभराव जैसी आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित बचाव दल की उपलब्धता से आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित

■ मतदान केंद्रों के युक्तियुक्त करण पर बनी सहमति, 40 मतदान केंद्रों के भवन बदलेंगे

■ 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन, 11 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावा-आपति



में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत 8 मतदान केंद्रों का स्थल परिवर्तन, एक का भवन परिवर्तन और 18 मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके अलावा 40 मतदान केंद्रों के अनुभाग परिवर्तन तथा 6 अनुभागों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया।

सभी प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया 2 नवंबर तक पूरी की जाएगी। एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, आवश्यक संशोधन एवं मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।



नवाचार को मिलेगी नई पहचान,युवाओं के नए विचारों पर 10 लाख का पुरस्कार



आर्मांत्रित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र से पांच-पांच विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 50 विजेता चुने जाएंगे। प्रत्येक विजेता को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के तहत कुल 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समाज एवं उद्योग जगत की

वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए नए और अभिनव विचार प्रस्तुत करने तथा रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसमें विद्यार्थियों के अलावा अन्य इच्छुक प्रतिभागी एवं नवाचारकर्ता भी हिस्सा ले सकते हैं।

पैरा-नरई अब बनेगा कमाई का जरिया,सीबीजी परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

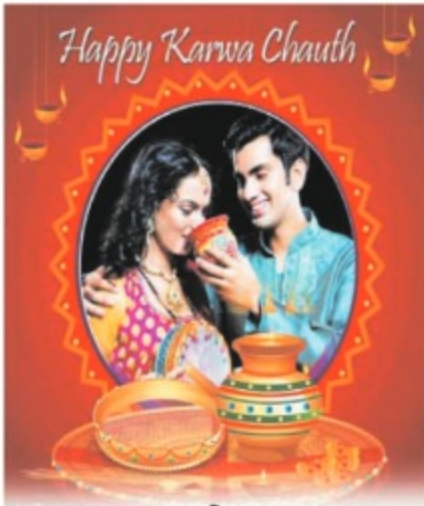


■ सीबीजी नीति के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक आयोजित

■ कंफ्रेस्ट बायोगैस परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय कंफ्रेस्ट बायोगैस (सीबीजी) मॉनिटरिंग समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ कंफ्रेस्ट बायोगैस नीति 2026 की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में सबसे पहले जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक यहां आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि पैरा-नरई जलाने से बचाव किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेषों का उपयोग बायोगैस उत्पादन में होने से किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने सीबीजी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा इनके प्रभावी

क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ सीबीजी नीति 2026 के प्रावधानों, जिला स्तरीय समिति के गठन के उद्देश्य एवं प्रमुख दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। परियोजनाओं के लिए आवश्यक फ़ीडस्टॉक के रूप में पैरा-नरई सहित कृषि अवशेष, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों की उपलब्धता तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने कहा कि पैरा-नरई का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित होने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और खेतों में नरई जलाने की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। बैठक में प्रत्येक विकासखंड में किसान उत्पादक संगठन (एफ़्सीओ) के गठन, किसानों एवं परियोजना संचालकों के बीच समन्वय तथा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी गोबरधन योजना से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। नगरीय निकायों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट एवं गोबर की नियमित आपूर्ति, परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को जिले में सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।



करवा चौथ के दिन इस मुहूर्त में करें सरगी

सुहागिन महिलाओं और अविवाहित लड़कियों के लिए करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और पति की लंबी आयु होती है। इस दिन सरगी की परंपरा को निभाया जाता है। सरगी सास अपनी बहु को देती है। हिंदू पंचांग अनुसार, करवा चौथ का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सुहागिन महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। रात को चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी से होती है। व्रत में सरगी का विशेष महत्व है।

सरगी की परंपरा

करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है। इसे सास अपनी बहु के लिए तैयार करती हैं। इसमें फल, मेवे, मिठाई और परांठे शामिल होते हैं, जिससे पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है। सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के बाद महिलाएं करवे (मिट्टी के पात्र) से जल अर्पित कर व्रत खोलती हैं।

सरगी में क्या शामिल करें?

करवा चौथ की सरगी में फलों को शामिल करना चाहिए। जैसे- सेब, केला, अमर, पीपता आदि। इसके अलावा सुखे मेवे, हलवा, मिठाई, दूध और दही समेत आदि चीजों को शामिल किया जा सकता है।

सरगी का महत्व

करवा चौथ के दिन सरगी की थाली में शामिल चीजों का सेवन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मान्यता है कि इस समय देवी-देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान जो चीज हम खाते हैं, तो वह हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं।

पूजा का शुभ मुहूर्त

करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। साल 2026 में पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक बताया जा रहा है। इस दौरान महिलाएं करवा माता की पूजा कर सकती हैं।

कब चांद निकलेगा

करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को चंद्रोदय रात करीब 8 बजकर 17 मिनट पर होने की संभावना है। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं।



मधुर प्यार और अखंड सुहाग का मंगल पर्व- करवा चौथ

पति की दीर्घायु और मंगल-कामना हेतु सुहागिन नारियों का यह महान पर्व है। करवा (जल पात्र) द्वारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण (उपवास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण उपवास के बाद का पहला भोजन) करने का विधान होने से इसका नाम करवा चौथ है। करवा चौथ और करक चतुर्थी पर्याय है। चन्द्रोदय तक निर्जल उपवास रखकर पुण्य संचय करना इस पर्व की विधि है। चन्द्र दर्शनोपरान्त सास या परिवार में ज्येष्ठ श्रद्धेय नारी को बायना देकर 'सदा सौभाग्यवती भव' का आशीर्वाद लेना व्रत की पहचान है। सुहागिन नारी का पर्व होने के नाते यथासंभव और यथाशक्ति न्यूनतम सोलह श्रृंगार से अलंकृत होकर सुहागिन अपने अंतःकरण के उल्लास को प्रकट करती है। पति चाहे जैसा हो पर पत्नी इस पर्व को मनाएगी अवश्य। पत्नी का पति के प्रति यह समर्पण दूसरे किसी धर्म या संस्कृति में कहा? पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्यतिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य-संचय करने के संकल्प को व्रत कहते हैं। व्रत और उपवास द्वारा शरीर को तपाना तप है। व्रत धारण कर, उपवास रखकर पति की मंगल कामना सुहागिन का तप है। तप द्वारा सिद्धि प्राप्त करना पुण्य का मार्ग है इसीलिए सुहागिन करवा चौथ का व्रत धारण कर उपवास रखती है। ब्रह्म मुहूर्त से चन्द्रोदय तक जल-

भोजन कुछ भी ग्रहण न करना करवा चौथ का मूल विधान है। वस्तुतः भारतीय पर्वों में विविधता का इन्द्रधनुषीय सौंदर्य है। इस पर्व के मनाने, व्रत रखने, उपवास करने में मायके से खाद्य पदार्थ भोजन, न भोजन आदि की रूढ़िवादी परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्नता के साथ प्रचलित हैं।

बायना देने-लेने, करवे का आदान-प्रदान करने, बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने-देने की सारी मान्यताएं अलग-अलग क्षेत्रों, जातियों/वर्गों में भले ही भिन्न हों, परंतु सभी का उद्देश्य एक ही है और वह है- पति का मंगल।

पश्चिमी सभ्यता में निहा रखने वाली सुहागिनों के लिए यह पर्व एक मार्गदर्शिका है। एक निर्देशिका है। वस्तुतः हिन्दू संस्कृति आदर्शों व श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण एक ऐसी संस्कृति है? जिसमें पारलौकिकता व आध्यात्मिकता की महत्ता है। चूंकि हिन्दू संस्कृति में पति-पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है इसीलिए व्रत-उपवास, पूजन-अर्चन इस जन्म-जन्मांतर के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। करवा चौथ व्रत पालन के महत्व के बारे में कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्ति दी गई है-

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायानोति दक्षिणाम। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात् व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है। दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। वस्तुतः पति अपनी पत्नी की श्रद्धा व आस्था देखकर कुछ इस तरह से अभिभूत हो जाता है कि वह पत्नी व

बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह के लिए कहीं अधिक संकल्पवान व निष्ठावान हो जाता है। हर सुहागिन अन्न-जल का परित्याग कर चांद की छवि दर्पण में देखकर और फिर अपने पति का मुखड़ा देखकर ईश्वर से यही मनोनीती मांगती है कि दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे। कभी चांद तो कभी सूरज बनकर निकलता रहे। हर भारतीय नारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, आदर्शों व परंपराओं पर गर्व करती है। करवा चौथ पर हर सुहागिन का हृदय अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने लगता है।



किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए करवा चौथ का व्रत?

करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। महिलाएं इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करते समय कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हालांकि यह व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, लेकिन कुछ स्थितियों में स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए।

गर्भवती महिलाएं

करवा चौथ के पर्व हर सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन गर्भवस्था के दौरान शरीर को अधिक पोषण की जरूरत होती है। वहीं करवा चौथ के व्रत में पूरे दिन कुछ भी खाना या पीना वर्जित होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करने की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था में भूखे रहना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ऐसे में महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए।

कुंवारी लड़कियां

करवा चौथ सुहाग का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार, इस व्रत को केवल सुहागिनों को ही रखना चाहिए। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसलिए कुंवारी लड़कियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए।

मासिक धर्म के दौरान

मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कोई भी पूजा-पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस दौरान महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए।

कमजोर या

अस्वस्थ महिलाएं

अगर कोई महिला किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त है या कमजोर है। ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे में महिलाओं को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए।



करवा चौथ की पूजा के बाद करवा का क्या करें?

दिवाली से पहले करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में करवाचौथ व्रत का बड़ा महत्व है। इस वर्ष करवा चौथ 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से दिनभर निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ को लेकर लोगों में कई सवाल भी होते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि, करवा चौथ की पूजा के बाद करवा का क्या करें?

कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को इधर-उधर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करने से माता गोरी नाराज होती है और आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में करवा को भूलकर भी इधर-उधर न फेंकें।

नदी में प्रवाहित करें - धार्मिक मान्यता के मुताबिक करवा चौथ की पूजा के बाद मिट्टी के करवा को पवित्र नदी या साफ तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। करवा को प्रवाहित करते समय या फिर पेड़ के नीचे रखते समय ध्यान रखें की यह कहीं से भी टूटे या खंडित न हो।

पवित्र पेड़ के नीचे रखें - अगर आप करवा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे पूजा के बाद किसी पवित्र पेड़ जैसे की पीपल, नीम, आम और बरगद के नीचे रख सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ होता है।

अगली साल के लिए रखें - कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को पूरे 1 साल तक संभालकर रखते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो ध्यान रखें कि इसे घर में किसी ऐसी जगह पर ही रखें जो साफ हो।

करवा चौथ व्रत के दौरान न करें ये काम

- करवा चौथ व्रत वाले दिन सुहागिन अपने श्रृंगार में सफेद और काले रंग की वस्तु का प्रयोग न करें। सुहागिन महिलाएं यदि करवा चौथ पर इन रंगों का उपयोग करती हैं तो उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है।
- करवा चौथ पर पूजा के बाद जब भी कोई श्रृंगार की वस्तु बच जाती है, तो उसे इधर उधर न फेंकें, बल्कि उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें।
- इस दिन धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचें। साथ ही किसी से कोई भी मनमुटाव न रखें और अपशब्द न कहें।
- व्रत पारण करने के बाद तामसिक भोजन ग्रहण न करें।

महिलाएं करें ये काम

हालांकि करवा चौथ की पूजा के समय भद्रा नहीं है फिर भी यदि महिलाओं को भद्रा का भय सता रहा है वो नीचे दिए गए मंत्र का जाप कर सकती हैं। धन्या दधमुखी भद्रा महामारी खरानना। कालारात्रिर्महारुद्रा विधिष्ठ कुल पुत्रिका। भैरवी च महाकाली असुराणां क्षयन्करी। द्वादशैव तु नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत। न च व्याधिर्भवेत् तस्य रोगी रोगात्प्रमुच्यते। गुह्यः सर्वेनफूला- स्यन्तु च विघ्नादि जायते। इस मंत्र के जाप से भद्रा का भय कम होता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म होती हैं।



करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सुख-दांपत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है।

पहली बार रखना है करवा चौथ व्रत....



जिन युवतियों का विवाह तय हो गया है, वे भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। इस व्रत में करवा माता, विघ्नहर्ता श्री गणेश, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करने का महत्व है। यह व्रत चतुर्थी के सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। चांद के निकलने का बाद पारण करके व्रत को पूरा करते हैं।

जिन युवतियों को पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना है, उनको पूजा सामग्री और मंत्र के बारे में जानना चाहिए।

करवा चौथ पूजा सामग्री

- करवा माता और गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति
- करवा माता के लिए चुनरी, नए कपड़े, गणेश जी और शंकर जी के लिए नए वस्त्र
- मिट्टी का करवा, एक दूधन, एक

- चांद देखने के लिए एक छलनी, लकड़ी की एक चौकी
- सोलह श्रृंगार की सामग्री, एक कलश, दीपक, रुई की बाती
- कपूर, अगरबत्ती, गेहूँ, लहुआ, 8 पुड़ियों की अठावरी
- अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, पान का पत्ता, कच्चा दूध, दही
- शंकर का बुरा, शहद, गाय का घी, रोली, कुमकुम
- मौली या रक्षासूत्र, मिठाई, एक लोटा या गिलास, दक्षिणा
- करवा चौथ व्रत कथा और आरती की एक पुस्तक

करवा चौथ पूजा मंत्र

करवा चौथ में माता पार्वती, विघ्नहर्ता गणेश और शिव जी की पूजा का विधान है, इसलिए उनके ही मंत्रों का उपयोग पूजन में होता है।

- मां पार्वती की पूजा का मंत्र - देहि

सौभाग्य आरोग्य देहि मे परम् सुखम्। सन्तान देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे॥

- गणेश पूजा मंत्र - वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥
- शिव पूजा मंत्र - ओम नमः शिवाय
- करवा चौथ चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र
- करवा चौथ को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा को कच्चा दूध, गंगाजल, अक्षत, फूल आदि से अर्घ्य देते हैं। इसके लिए आपको अर्घ्य देने के मंत्र का उच्चारण करते हैं। गगनार्णवमाणिव्य चन्द्र दाक्षायणीपते। गुहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेशप्रतिरूपक॥

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने किया ?6.61 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन, वनांचल क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ

विकास कार्यों से बदल रही पंडरिया विधानसभा के गाँव की तस्वीर, पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 6.61 रूपए करोड़ से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

कवर्धा। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास एवं जनसुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रतिबद्ध पंडरिया विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से निरंतर विकास कार्यों का सीगात मिल रही है। विधायक भावना बोहरा ने पांडतराई मंडल अंतर्गत 6 करोड़ 61 लाख 48 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने 6 करोड़ 12 लाख 10 हजार की लागत से भगतपुर से घोघरा तक 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग रही इस सड़क के निर्माण से भगतपुर, घोघरा, मिन्हीरी, खैरझिटी और वनांचल क्षेत्र कुई-कुंकदुर सहित आस-पास के कई



ग्रामवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषकर इन क्षेत्रों में सब्जी की फसल उत्पादन करने वाले किसानों व व्यापारियों को अब पांडतराई तक सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी इसके साथ जिला मुख्यालय आने-जाने में भी लम्बी दूरी तय करके जाने की असुविधा से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पाटो में 11 लाख 69 हजार की लागत से

आंगनवाड़ी भवन तथा ग्राम खैरझिटी पुराना में 11 लाख 69 हजार की लागत से आंगनवाड़ी भवन, 14 लाख रु की लागत से चेकडेम, 7 लाख रु की लागत से शाला में अतिरिक्त कक्ष और 5 लाख रु. की लागत से निर्मित अटल डिजिटल सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही बच्चों को बेहतर



शैक्षणिक वातावरण, महिलाओं एवं नौनिहालों को सुविधाजनक सेवाएं तथा डिजिटल सेवाओं को सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा का सर्वांगीण विकास और प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हमारा प्रयास है कि पंडरिया विधानसभा के वनांचल

क्षेत्रों से लेकर हर गांव-गांव तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचें, जिससे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन भाजपा सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए विकास कार्यों

को निरंतर गति दे रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को बेहतर सुविधाएं मिलें और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भगतपुर से घोघरा तक सड़क निर्माण से ग्रामीणों, किसानों और व्यापारियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, वहीं आंगनवाड़ी भवनों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। खैरझिटी पुराना में चेकडेम का निर्माण जल संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। ये सभी कार्य ग्रामीणों की आवश्यकताओं और क्षेत्र की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हैं।

विधायक भावना बोहरा ने आगे कहा कि पंडरिया विधानसभा में विकास और जनसुविधाओं के विस्तार का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। हमारा संकल्प है कि प्रत्येक गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए क्षेत्र को शिक्षा, आधारभूत संरचना, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और क्षेत्रवासियों के जीवन को अधिक सुगम, सुविधाजनक एवं समृद्ध बनाना ही हमारी प्रतिबद्धता है। भावना बोहरा ने कहा कि विगत वर्षों में पंडरिया विधानसभा में जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। गांव गाँव और वनांचल तक सड़कों का जाल बिछ रहा है। 1000 हजार करोड़ से अधिक के विकास व

अभोसंरचना निर्माण कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिली है। पेयजल और सिंचाई एवं कृषि के लिए 300 करोड़ से अधिक के पेयजल एवं जल आवर्धन परियोजनाएं अपना आकार ले रहीं हैं, चौक-चौराहों का सौन्दर्यीकरण, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, वनांचल क्षेत्रों तक सुविधाओं की पहुंच तथा पंडरिया विधानसभा के प्रत्येक गाँव तक सड़क, नाली,पुल-पुलिया, बिजली, प्रकाश व्यवस्था व पेयजल सुविधा जैसे जनसुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों से पंडरिया नगर निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

बस्तर दशहरा का समापन राजमहल परिसर में हर्ष फायरिंग और कलश यात्रा के साथ माता मावली को दी गई आत्मीय विदाई

जगदलपुर, ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के 75 दिवसीय विशाल धार्मिक अनुष्ठानों का विधिवत समापन मंगलवार को माता मावली की डोली और मां दैतधरी के छत्र की ससम्मान विदाई के साथ हुआ। जगदलपुर के राजमहल परिसर स्थित ऐतिहासिक मां दैतधरी मंदिर में परंपरागत विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा-अर्चना संपन्न की गई। इसके उपरांत पुलिस के जवानों ने हर्ष फायरिंग कर माता को गरिमामयी सलामी दी। विदाई के इस पावन और भावुक क्षण में सिर पर कलश धारण किए महिलाओं ने मोल गीतों के साथ माता को अत्यंत आत्मीय विदाई दी, जिसमें संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। माता की इस ऐतिहासिक विदाई यात्रा के लिए दैतधरी मंदिर



परिसर और विदाई मार्ग को लगभग डेढ़ किंटल गेदे, गुलाब और बासंती फूलों की सुंदर पंखुहियों से सजाया गया था। डोली के प्रस्थान के समय उपस्थित जनसमुदाय और ब्रह्मलुओं ने जयकारों के बीच माता पर गुलाब की पंखुहियों की पुष्पवर्षा कर आस्था के साथ विदा किया। इस धार्मिक विधान में बेल और सागौन को लकड़ी से निर्मित करीब 15 साल पुरानी डोली आकर्षण का मुख्य केंद्र रही, जिसमें करीब चार किलो चांदी, दोनों ओर चांदी की

प्रतिमाएं और 45 चांदी के गुब्बे जुड़े हुए हैं। परंपरा अनुसार बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव और ब्रह्मलुओं ने माता की करीब 20 किलो वजनी डोली को कंधों पर उठाकर जिया डेरा तक पहुंचाया, जिसके बाद डोली और छत्र को देतावाड़ा के लिए विदा किया गया। इस पावन अवसर पर मंदिर पहुंचे दर्शनार्थियों को 76 किलो बूंदी और लड्डू से तैयार किए गए 5,000 से अधिक पैकेटों में प्रसाद का वितरण किया गया।

वोट बचाओ –देश बचाओ, वोट चोरी को लेकर बैठक संपन्न केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं कांग्रेस प्रभारी ने प्रेस को सम्बोधित किया

नारायणपुर – अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में हो रहे वोट चोरी को लेकर व्यापक स्तर पर जन आंदोलन कर शुरुआत कर चुकी है और आने वाले समय में देश के कोने कोने में सभा कर गाँव गाँव में बाजारों में नुकड़ सभा कर अंतिम व्यक्ति तक वोट चोरी मुक्त में घाघली को लेकर जाएगी और उसके मत को भारतीय जनता पार्टी कैसे चोरी करती है उसका मत कहा जा रहा है इससे बताने का निर्णय लिया गया है, महाराष्ट्र से आये पूर्व विधायक एवं एआईसीसी पर्यवेक्षक राजेश धोन्डी राम ने राजीव भवन पहुंच कर जिला कांग्रेस एवं समस्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का बैठक लिया बैठक में उन्होंने ने कहा की भारतीय जनता पार्टी सिर्फवोट करने तक ही सिमित नहीं खुदक के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाना, दोहरी पंजीकरण, चुनाव सम्बंधित आकड़े में



पारदर्शिता श्रद्धा और दृढ़ज्ञान की कार्यप्रणली चुनाव आयोग के आचरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे है 7 फरवरी 2025 महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 39 लाख वोटर अचानक जुड़ने का सवाल उठये, वही अगस्त 2025 में महादेव पुरा कर्नाटक मे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोहरा पंजीकरण आमाम्य या सौंदध्य तस्वीर फर्म -6 का दुरुल्योगे वो उजागर किया इसी तरह

नवम्बर 2025 को हरियाणा मे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को उजागर किया था, वही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी इंडियन एक्सप्रेस समाचार को बताया की फर्म - का दुरुपयोग किया गया था और अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर 14 बार शिकायत दर्ज करवाया जिससे पुरा देश ने चुनाव प्राणली और वोट चोरी को जाना और समझा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा मे

नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने वोट चोरी को लेकर इण्डिया गठबंधन को एक किया और आंदोलन किया जिससे आज देश मे जेन जी ने आंदोलनरत है और कांग्रेस पुरा इंडिया गठबंधन के साथ 1 नवम्बर को राम लीला मैदान दिल्ली मे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने जा रही है आगे राजेश राउटर ने कहा की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज और नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्ति किया जाता रहा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया कानून लाकर केबिनेट मंत्री को अध्यक्ष बनाकर इस प्रक्रिया को बदला है, ताकि अपने पसंद से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सके और वोट चोरी कर सके, कांग्रेस निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती है साथ ही हद्दहद्द को स्थिति और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा का मांग करती है।

संभावित बाढ़ को लेकर सभी विभाग रहें अलर्ट, राहत एवं बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करें—कलेक्टर विश्वदीप

बीजापुर -कलेक्टर विश्वदीप ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में संभावित बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव की तैयारियों, आगामी धान खरीदी, बस्तर मुये अधिधान सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहकर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने तथा लॉन्च प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
“संभावित बाढ़ को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश”—कलेक्टर ने नदी किनारे एवं संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में विशेष सतर्कता बतने, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों एवं जरूरतमंद परिवारों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में एनडीआरएफ के



30 जवानों के पहुंचने तथा राहत एवं बचाव के लिए पर्याप्त नावों की उपलब्धता की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने पर्याप्त वाहन, नाव, राहत भवन, अस्थायी टेंट एवं आवश्यक मशीनरी को व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बिजली, शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को सतर्क रहने तथा कोटवारों एवं पंचायत सचिवों के माध्यम से ग्रामीणों तक समय पर सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही फसल एवं मकान क्षति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने को कहा।

बस्तर मुये अभियान के तहत 15 नवंबर तक सभी पात्र हितग्राहियों को करें लाभान्वित—कलेक्टर ने बस्तर मुये अभियान की समीक्षा करते हुए चिन्हांकित गांवों में सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, पीएम किसान सम्मान निधि, एनआरएलएम, श्रमिक कार्ड, बैंक खाता, वनाधिकार पट्टा, मातृ वंदना योजना सहित जन्म, मृत्यु, विवाह, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र तथा आधार एवं राशन कार्ड

लॉकिंग के लॉन्च कार्यों को 15 नवंबर तक पूर्ण करने को कहा। प्रत्येक पंचायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यकता अनुसार विशेष शिविर लागू के निर्देश भी दिए।बीबी-जी एम जी के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से पहले पूर्ण करें सभी व्यवस्थाएं—आगामी धान खरीदी की तैयारियों को समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों में पेयजल, सौचालय, जल निकासी, कांटा-बांट, छाया एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं 15 नवंबर से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। नवीन धान खरीदी केंद्र तिमिापुर की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

बस्तर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की लॉन्च मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच, छत्तीसगढ़ ने अपनी आवाज बुलंद की। बस्तर ब्लॉक अध्यक्ष बेदमती जोशी एवं ब्लॉक उपाध्यक्ष दीर्घाका कोरसे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने रैली निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा विभागीय सचिव के नाम ज्ञापन नाथब तहसीलदार को सौंपा गया। संयुक्त मंच ने मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उनके निराकरण को दिशा में ठोस पहल कार्यकर्ताओं की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों



आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की देखभाल सहित विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली इन कार्यकर्ताओं की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों

में विशेष महत्व रखती हैं। इसके बावजूद नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, पदोन्नति और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं। इन्हें समस्याओं को लेकर संयुक्त मंच ने रैली के माध्यम से अपनी मांगें शासन तक पहुंचाईं। संयुक्त मंच ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने तथा

सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत करने की मांग की है। नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 30 हजार रुपये और सहायिकाओं को 25 हजार 500 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने की मांग भी की गई है। मंच का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच परिवार की जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में सम्मानजनक मानदेय और नियमित वृद्धि की व्यवस्था से कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को आर्थिक राहत मिल सकती है। ज्ञापन में पैपैन, समूह बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है।

89.56 लाख का अर्दन चेकडेम दो साल में क्षतिग्रस्त ! निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के घटियारीन नाल में वर्ष 2024 में हुआ था निर्माण, मरम्मत के बाद भी ढांचे में दरारें; जांच और जवाबदेही की मांग

धमतरी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के उद्देश्य से लाखों रुपये खर्च कर निर्माण कार्य कराए जाते हैं, ताकि जंगलों में पानी की उपलब्धता बढ़े और वन्यप्राणियों को भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन जब लाखों रुपये की लागत से बना निर्माण कुछ ही वर्षों में क्षतिग्रस्त होने लगे, तो उसकी गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक मामला धमतरी जिले के बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अंतर्गत घटियारीन नाल कश्च क्रमांक 467 से सामने आया है, जहां वर्ष 2024 में करीब 89.56 लाख रुपये की लागत से निर्मित अर्दन चेकडेम के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के महज एक से दो वर्ष के भीतर ही डैम टूटने लगा। इसके बाद मरम्मत कार्य भी कराया गया, लेकिन अब भी सीमेंट के ढांचे में



कई जगह दरारें दिखाई देने की बात सामने आ रही है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता और मरम्मत कार्य की प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
89.56 लाख खर्च, फिर इतनी जल्दी कैसे क्षतिग्रस्त हुआ डैम?—जानकारी के अनुसार, घटियारीन नाल कश्च क्रमांक 467 में लगभग 32 हेक्टेयर क्षेत्र से संबंधित नाले पर वर्ष 2024 में अर्दन चेकडेम का निर्माण कराया

गया था। इस कार्य पर 89.56 लाख रुपये खर्च किए जाने की जानकारी है। चेकडेम का उद्देश्य वर्षा जल का संचयन कर जल संरक्षण को बढ़ावा देना और वन क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण लंबे समय तक अपनी मजबूती बरकरार नहीं रख सका। यदि निर्माण कार्य निष्पत्ति तकनीकी



मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप हुआ था, तो इतने कम समय में संरचना के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच होनी चाहिए। हालांकि, डैम के क्षतिग्रस्त होने के वास्तविक कारणों का पता तकनीकी जांच के बाद ही चल सकेगा।
मरम्मत के बाद भी दरारें, गुणवत्ता पर सवाल—ग्रामीणों के अनुसार, डैम के क्षतिग्रस्त होने के बाद विभाग की ओर से मरम्मत कार्य भी कराया गया। लेकिन



मरम्मत के बाद भी सीमेंट के ढांचे में दरारों के निशान दिखाई देने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मरम्मत के दौरान सामने की ओर के दो सीटिओ को दोबारा बनाया गया, जबकि अन्य स्थानों पर मौजूद दरारों को सीमेंट का लेप लगाकर ठीक करने का प्रयास किया गया। हालांकि, कुछ हिस्सों में दरारें अब भी स्पष्ट नजर आने का दावा किया जा रहा है। यदि मरम्मत के बाद भी संरचना में दरारें मौजूद हैं,



तो यह जांच का विषय है कि मरम्मत निष्पत्ति तकनीकी मानकों के अनुरूप हुई या नहीं। साथ ही, निर्माण और मरम्मत कार्य में उपयोग की गई सामग्री तथा अपनाई गई तकनीकी प्रक्रिया की जांच भी जरूरी है।
जंगल के भीतर निर्माण, निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण पर सवाल—वन क्षेत्र में निर्मित जल संरचनाओं की उपयोगिता केवल निर्माण तक सीमित नहीं होती,

बल्कि उनकी मजबूती और दीर्घकालिक उपयोगिता भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का पालन, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, कार्य की निगरानी और समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक है। घटियारीन नाल में लाखों रुपये की लागत से बने अर्दन चेकडेम के क्षतिग्रस्त होने और मरम्मत के बाद भी दरारें दिखाई देने के दावों ने इन पहलुओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग इस मामले में तकनीकी जांच कराता है या नहीं और निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।
डीएफ ओ से नहीं हो पाई चर्चा—मामले को लेकर जिले के वनमंडलाधिकारी (डीएफ ओ) से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। हालांकि, खबर तैयार किए जाने तक उनसे विस्तृत चर्चा

नहीं हो सकी। डीएफओ ने बैठक में व्यस्त होने की जानकारी दी। ऐसे में विभाग का आधिकारिक पक्ष और निर्माण एवं मरम्मत कार्य से संबंधित तकनीकी जानकारी सामने आना अभी बाकी है।
अब जांच और जवाबदेही का इंतजार—89.56 लाख रुपये की लागत से निर्मित अर्दन चेकडेम के कम समय में क्षतिग्रस्त होने तथा मरम्मत के बाद भी दरारें दिखाई देने के मामले में निष्पक्ष तकनीकी जांच की आवश्यकता है। निर्माण की वास्तविक स्थिति, मरम्मत की गुणवत्ता, खर्च की गई राशि और कार्य की निगरानी से जुड़े अभिलेखों की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कराएगा और यदि निर्माण या मरम्मत में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी?